● वर्ष-3
● अंक-116
रायपुर, शनिवार
23 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› सर्दियों में स्किन ड्राई और....

विष्णु देव साय सरकार में नौ भाजपा विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

राम-लखन और श्याम से लेकर लक्ष्मी तक, विष्णु सरकार की कैबिनेट में मंत्री बने ये 9 विधायक

रायपुर। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल गठन हो गया है। आज राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने नौ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में पुराने के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी ने विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली।

संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में सीएम समेत अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में साय कैबिनेट में तीन सदस्य हैं। इसमें मुख्यमंत्री साय और दो डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने राज्य में बीजेपी का सरकार बनने के बाद 13 दिसंबर को शपथ ली थी। आइए जानते हैं उन नौ विधायकों के बार में जो साय मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं।

विधायक बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल आठवीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। वह अविभाजित मध्यप्रदेश में पटवा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, इसके बाद रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास को 67,919 वोटों से हराया। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल का जन्म एक मई 1959 को रायपुर में हुआ। कॉमर्स और आर्ट्स दोनों विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बृजमोहन अग्रवाल ने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की है।

रामविचार नेताम

लगातार छठवीं बार विधायक निर्वाचित हुए भाजपा के कद्दावर नेता रामविचार नेताम ने मंत्री पद की शपथ ली। बलरामपुर के ग्राम सनावल के रहने वाले राम विचार नेताम राज्यसभा के सदस्य और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा ने उन्हें रामानुजगंज विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस के डा. अजय तिर्की को हराया। नेताम साल 1990 से लगातार छठवीं बार विधायक चुने गए हैं।

केदार कश्यप

नारायणपुर विधानसभा सीट से चुने गए विधायक केदार कश्यप ने विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की। छात्र जीवन से

ही केदार कश्यप राजनीति में सक्रिय हैं। वह कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व सांसद स्व. बलीराम कश्यप के बेटे हैं। उनका जन्म पांच नवंबर 1974 को हुआ। बस्तर जिले के भानपुरी के गांव फरसागुड़ा के रहने वाले केदार कश्यप भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। केदार कश्यप 2003 में पहली बार विधायक चुने गए। 2008 में दूसरी और 2013 में तीसरी बार विधायक बने।

दयालदास बघेल

नवागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार को हराकर दयालदास बघेल एक बार फिर विधानसभा में पहुंचे हैं। सरपंच के पद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले दयालदास बघेल ने विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। बघेल ग्राम पंचायत कुरा के सरपंच भी रहे हैं। साल 2003 में नवागढ़ विधानसभा सीट से बघेल पहली बार विधायक चुने गए थे। साल 2008 और 2013 में भी वह विधायक बने। रमन सिंह सरकार में बघेल वाणिज्य, उद्योग, सहकारिता संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं।

लखन लाल देवांगन

कोरबा जिले की कोरबा विधानसभा सीट से लखन लाल देवांगन विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के तीन बार के विधायक और दिग्गज मंत्री जयसिंह अग्रवाल को 26,790 वोटों से मात दी थी। लखनलाल देवांगन दो बार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कटघोरा विधानसभा सीट से विधायक और कोरबा निगम के महापौर भी रह चुके हैं। लखन लाल का जन्म 12 अप्रैल 1962 को कोरबा में हुआ। लखन ने बीए प्रथम वर्ष तक की शिक्षा हासल की।

श्याम बिहारी जायसवाल

सरगुजा संभाग के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने शपथ ली। जायसवाल पहले में जिला पंचायत खड़गवां के अध्यक्ष भी रहे हैं। श्याम बिहारी जायसवाल भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। साल 2013 के चुनाव में वह पहली बार विधायक चुने गए थे। 2018 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि हार का अंतर कम था।

ओपी चौधरी

रायगढ़ से भाजपा विधायक और पूर्व आईएएल अधिकारी ओपी चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। ओपी चौधरी प्रशासनिक कौशल में माहिर हैं। ओपी चौधरी पहली बार ही विधायक निर्वाचित हुए हैं। साल 2018 में आईएएस अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी।

लक्ष्मी राजवाड़े

विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के गठन में आठवें नंबर पर विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्री पद की शपथ ली। लक्ष्मी पहली बार विधायक चुनी गई हैं। विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री हैं। भटगांव विधानसभा सीट से महिला मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाली लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस से दो बार के विधायक रहे पारस नाथ राजवाड़े को करीब 44 हजार मतों से हराया था।

टंकराम वर्मा

विधायक टंकराम वर्मा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वर्मा बलौदाबाजार सीट से पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं। मंत्री बनने वाले टंकराम वर्मा ने शिक्षक की नौकरी छोड़ राजनीति में एंट्री की थी। टंकराम वर्मा ने एलएलबी की हुई है। वे सबसे पहले तिल्दा से जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे, इसके बाद रायपुर जिला पंचायत में उपाध्यक्ष भी रहे। वर्मा पिछले 30 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं।

भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की बैठक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के पदाधिकारियों को राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम पर बड़ा अभियान चलाने का मंत्र दे सकते हैं। यह आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता है और पार्टी की जीत की संभावनाओं को मजबूत कर सकता है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के टॉप पदाधिकारियों की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, महासचिव, सचिव और विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष-प्रभारी जैसे लगभग 50 पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। यह बैठक कल शनिवार को भी जारी रहेगी।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में विभिन्न प्रदेशों में मिले चुनाव परिणाम की समीक्षा की जा सकती है। अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन संबंधित तैयारियों को लेकर चर्चा की जा सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री इस मुद्दे को जन-जन तक ले जाने की अपील कर सकते हैं। देश के हर बूथ तक इस संदेश को ले जाने के लिए विशेष योजना तैयार की जा सकती है, जिससे राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को हर मतदाता तक ले जाया जा सके। बैठक में विकसित भारत यात्रा के विषय में भी चर्चा की जा सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व भाजपा के टॉप अधिकारियों की इस बैठक को बेहद महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष की लामबंदी और जातिगत जनगणना-ओबीसी समुदाय को हिस्सेदारी के विपक्ष के मुद्दों की काट खोजने के लिए भी पार्टी नेता इस मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। माना जा रहा है कि इसी दो दिवसीय बैठक में भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों की दिशा को अंतिम रूप दे देगी।

इसके पहले इसी महीने 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए इंडिगो एयरलाइंस अपनी पहली उड़ान की शुरुआत करनी जा रही है। इससे न केवल अयोध्या के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की उद्घाटन समारोह की तैयारी ज़ारी है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधान मंत्री करने वाले है।

प्रमुख समाचार

भारत के 11 राज्यों तक फैल चुका कोरोना का जेन.1 वैरिएंट

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना महामारी (कोविड-19) के 70 करोड़ से अधिक मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अब तक 69.58 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच 41 देशों में कोविड-19 के नए वैरिएंट जेएन.1 का पता लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक इस नए वैरिएंट के 7,300 से अधिक मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। भारत में भी छह.1 वैरिएंट के कई मामले आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने जेएन.1 कोरोना वायरस स्ट्रेन का वर्गीकरण वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर किया। डब्ल्यूएचओ ने कहा, इससे आम जनता के स्वास्थ्य को बड़ा खतरा नहीं है। समाचार एजेंसी- रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 का जेएन.1 वैरिएंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे सकता है। दूसरे कोविड-19 वैरिएंट की तुलना में यह अधिक आसानी से फैल सकता है। हालांकि, अभी तक बेहद गंभीर बीमारी के कोई संकेत नहीं मिले हैं। राजस्थान के कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक महीने का बच्चा कोरोना संक्रमित हो गया। वहीं, जोधपुर में भी एक युवती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वह पांच दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से लौटकर आई थी।

ईडी ने केजरीवाल को भेजा तीसरी बार समन

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजा है। ईडी द्वारा शुक्रवार को भेजे गए समन में केजरीवाल को तीन जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल 10 दिन विपश्यना के लिए पंजाब चले गए हैं। बता दें कि इससे पहले ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बीते सोमवार को उन्हें समन जारी करके गुरुवार को बुलाया था। इस पर केजरीवाल ने अपने वकीलों द्वारा कहा गया कि यह सिर्फ 2024 में लोकसभा चुनाव के अंतिम महीनों में सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए है। समन के समय पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा कि आपके समन का समय मेरी सोच को और मजबूत करता है कि मुझे भेजे जा रहे समन किसी उद्देश्य या तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं हैं बल्कि पूरी तरह से प्रचार के साथ-साथ देश में बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव के अंतिम कुछ महीनों में सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है।

मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा रहा हूं-बजरंग पुनिया

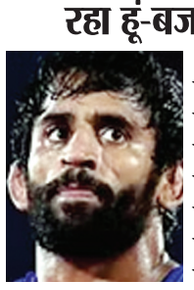

नई दिल्ली। पहलवान साक्षी मलिक द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के रूप में बृज भूषण के करीबी संजय सिंह के चुनाव का विरोध करने के एक दिन बाद, बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी को अपना पद्म श्री पुरस्कार लौटाते हुए एक पत्र लिखा। बजरंग पुनिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री को लौटा रहा हूं। यह घोषणा करने के लिए यह सिर्फ मेरा पत्र है। यह मेरा बयान है। बृजभूषण सिंह के वफादार संजय सिंह 15 में से 13 पद जीतकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। संजय सिंह के चुनाव के बाद साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें साक्षी ने विरोध स्वरूप खेल छोड़ने की घोषणा की। साक्षी ने कहा कि हमने दिल से लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर बृज भूषण जैसे व्यक्ति, उनके बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी को डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष चुना जाता है, तो मैं कुश्ती छोड़ देती हूं। आज से आप मुझे मैट पर नहीं देखेंगे।

संजय सिंह को नही मिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ मामला वास्तविक है और प्रस्तुत सबूत कथित मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता दिखाते हैं। प्रस्तुत सामग्री से पता चलता है कि संजय सिंह कथित मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधियों में शामिल थे। इस बीच, संजय सिंह के वकीलों ने अदालत से कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ पैसे का कोई मामला नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयानों पर भरोसा किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। उन्हें 4 अक्टूबर को दिल्ली में उनके घर की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

पुंछ हमले के पीछे चीन-पाक की बड़ी साजिश का खुलासा

नई दिल्ली। पाकिस्तान और चीन भारतीय सेना पर लद्दाख सीमा से वापस कश्मीर में सैनिकों को फिर से तैनात करने के लिए दबाव बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकी गतिविधियों को एक्टिव करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। यह खुलासा पुंछ में एक आतंकवादी हमले में पांच सैनिकों की हत्या के बाद हुआ है। सूत्रों का कहना है कि हिंसा में यह बढ़ोतरी इस्लामाबाद और बीजिंग की समन्वित रणनीति का हिस्सा है। एन निजी मीडिया हाउस ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है पाकिस्तान ने सुरक्षा बलों पर हमले शुरू करने और प्रतिक्रिया भड़काने के उद्देश्य से पुंछ के इलाकों में 25-30 आतंकवादियों की घुसपैठ कराई है। सूत्रों के अनुसार, चीन गलवान में 2020 के सीमा गतिरोध के बाद लद्दाख में भारत की बढ़ती सैन्य उपस्थिति से निराश होकर, भारतीय संसाधनों को वापस कश्मीर की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि पाकिस्तान, संभावित चीनी समर्थन के साथ, पश्चिम में आतंकवाद को फिर से शुरू करके भारत को पूर्वी मोर्चे पर दबाव कम करने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है। यह संदेह भारत द्वारा 2020 में पुंछ से लद्दाख तक एक विशेष आतंकवाद विरोधी बल, राष्ट्रीय राइफल्स की तैनाती से उत्पन्न हुआ है।

विपक्षी गठबंधन से अलग राह खोज रही है कांग्रेस?

आलोक कुमार

प्रचंड बहुमत से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए बने विपक्ष के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव एलायंस (इंडिया) की स्थिति डांवाडोल है। 19 दिसंबर को दिल्ली में संपन्न बैठक से पहले और बाद में आए बयानों से कई गंभीर विरोधाभास उभरकर सामने आ रहे हैं। भाजपा विरोधी मतों का मालिकाना हक खुद तक सुरक्षित रखने की कांग्रेसी चाह ने गठबंधन के मौजूदा स्वरूप में बने रहने पर संशय पैदा कर दिया है। इसीलिए अब तक गठबंधन के संयोजक के नाम पर दुविधा बनी हुई है। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते फिलहाल गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के पास है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं को अगले दस दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी 543 सीटों पर बीजेपी से मुकाबला कर सकने वाले मजबूत उम्मीदवार ढूंढने हैं। उन पर पंद्रह जनवरी तक अंतिम निर्णय कर लेना है, ताकि चुनाव तैयारी के लिए उम्मीदवार व दलों को कम से कम तीन महीने का समय तो मिल पाए। विपक्षी धुरी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि इस असाध्य लक्ष्य का पूरा हो पाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन के 28 दलों का चरित्र एक सा नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, अलग अलग किस्म की चुनौतियां हैं। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने पिछले महीने अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़कर जीत हार का अनुभव ले लिया है। उम्मीद के लिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव का ताजा परिणाम सामने है। कांग्रेस पार्टी ने बीच चुनाव में दो बार के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ 卐बीजेपी की बी टीम卐 होने की डुगडुगी बजाई। मतदाताओं को सप्रमाण समझाया कि चंद्रशेखर राव बीजेपी से मिले हुए हैं। राव का तीसरी बार मुख्यमंत्री होना राज्य में बीजेपी के परोक्ष शासन को स्वीकार करना है। यह बात मतदाताओं को समझ में आ गई। अल्पसंख्यक और प्रखर बीजेपी विरोधी मतदाता कांग्रेस के पक्ष में एकत्रित हो गये। परिणामस्वरूप संघ के विद्यार्थी परिषद से संगठन का गुर सीख कांग्रेस की राजनीति में आये रेवंत रेड्डी मतदाताओं के दिलो दिमाग पर छा गए। कांग्रेस आलाकमान ने बेहिचक उनके सिर मुख्यमंत्री का ताज सजा दिया। नतीजतन चुनाव पूर्व विपक्षी राजनीति की धुरी बनने की चाहत रखने वाले भारत राष्ट्र समिति के सर्वेसर्वा चंद्रशेखर राव को अब वानप्रस्थ आश्रम की राह पकड़नी पड़ी।

तेलंगाना चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के पास यह विकल्प मजबूती से खुला है कि वह इंडिया गठबंधन के संदिग्ध पार्टनर्स की फौज के बीच माथापच्ची करने के बजाय आगामी आम चुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरे और बीजेपी का एकमात्र विकल्प होने का दम भरते हुए बाजी जीतने का प्रयास करे। इस पहलू पर 21 दिसंबर को दिल्ली में संपन्न कांग्रेस केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में गंभीर मंत्रणा हुई है। कांग्रेस ने आम चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा पार्ट दो पूरा करने का फैसला लिया है। इंडिया गठबंधन का इतिहास यह है कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर जून में बैठक हुई। तब कांग्रेस समेत सिर्फ 16 दल शामिल हुए थे। दूसरी बैठक कर्नाटक में बीजेपी को हराकर सरकार बनाने से उत्साहित कांग्रेस शासित राज्य बेंगलूरु में हुई। कांग्रेस पार्टी की पहल पर उसमें 28 राजनीतिक दल शामिल हुए। बीजेपी को सत्ता से हटाने का सपना पाले राजनीतिक दलों का कारवां बड़ा हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका नामकरण इंडिया कर दिया। अंग्रेजी नाम वाले इंडिया और गठबंधन में हाशिए पर धकेले जाने की आशंका से नीतीश कुमार असहज हो उठे। जनता दल यू की ओर से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग लगातार उठ रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री होने के इसी ख्वाब को हासिल करने के लिए बीते अगस्त महीने में बीजेपी का दामन छोड़कर लालू प्रसाद की पार्टी को साथ लेकर सरकार बनाने का फैसला लिया था। लेकिन ऐसा सपना नीतीश का ही नहीं है। बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल कई नेताओं के सपने में प्रधानमंत्री की कुर्सी है। लिहाजा पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश के ख्वाब की काट के लिए गठबंधन की ताजा बैठक में ममता बनर्जी ने जोरदार पासा फेंका। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाल दिया। ममता के इस दांव से नीतीश के साथ कांग्रेस पार्टी भी असहज हो गई। आलाकमान के तौर पर सोनिया गांधी परिवार को ही सर्वेसर्वा मानने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के प्रत्याशी राहुल गांधी की जगह खड़गे का नाम सामने आते ही बगले झांकने लगे। इसे रफू करने के लिए उसके बाद हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी के नेतृत्व को प्रतिष्ठापित रखने का फैसला लिया गया। इसके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में पश्चिम से पूरब तक भारत जोड़ा यात्रा के दूसरे चरण की तत्काल तैयारी शुरु करने का फैसला लिया गया। तृणमूल नेता ममता से पहले गठबंधन के नेता उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की पकड़ को शिथिल करने के लिए नीतिश कुमार को संयोजक बनाने का शिगूफा छोड़ दिया था। इंडिया गठबंधन में जारी इस दांव प्रतिदांव से सहमी कांग्रेस का एक मन कह रहा है कि वह किसी और के भरोसे आम चुनाव में उतरने के बजाए खुद को ही मजबूत करने पर जोर दे। वैसे भी गठबंधन में दलों की संख्या बढने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ही उठाना पड़ सकता है। मसलन कांग्रेस ने कम सहयोगी दलों के साथ 2019 का पिछला आम चुनाव 421 सीटों पर लड़ा था। उनमें से 52 सीटों पर जीत हुई थी। अब जब विपक्षी गठबंधन के बाकी दलों से जीत की ज्यादा संभावना उसके साथ है, तो गठबधन के नाम पर कम सीटों पर लड़ना उसके लिए कहीं से बुद्धिमत्ता भरी बात नहीं हो सकती। इस साल हुए हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है। उसके मद्देनजर भी खुद की नीतियों पर फोकस होकर आम चुनाव में उतरने का दबाव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में भले ही कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है मगर ईवीएम में पड़े मतों की संख्या यह बताने के लिए काफी है कि इन राज्यों से लोकसभा की ज्यादा सीटें पाने का कांग्रेस पार्टी पर हौसला बना हुआ है।

नक्सलियों के भारत बंद का असर नहीं, चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस बल

■ 5 किलो के आईईडी को फोर्स ने किया निष्क्रिय

बीजापुर। नक्सलियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है।जिसका मिला जुला असर बस्तर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। गुरुवार शाम बीजापुर आवापल्ली मार्ग पर नक्सलियों ने उत्पात मचाया था।जिसके कारण शुक्रवार को आवापल्ली मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप रहा।नक्सलियों ने इस मार्ग पर सड़क को कई जगहों पर खोदा था।इसके बाद बड़े पेड़ों को काटकर सड़क पर गिरा दिया था। जिसके कारण सड़क मार्ग पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रुक गई थी।

नक्सलियों ने सुरक्षा पार्टी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से पगडण्डी रास्ते पर 5 किलो का आईईडी कुकर में प्लांट किया था।जिसमें प्रेशर स्वीच लगाया गया था। जिसे नक्सल अभियान में निकले डीआरजी की पार्टी एवं बीडीएस बीजापुर की टीम द्वारा आईईडी बरामद कर मौके पर निष्क्रिय किया गया।

नक्सलियों की हरकत के बाद बीजापुर आवापल्ली मार्ग में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। जिसकी सूचना पुलिस को तत्काल दे दी गई थी।लेकिन सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए पुलिस की टीम 14 घंटे बाद आई।14 घंटे बाद सड़क मार्ग पर गिरे पेड़ को हटाने का काम शुरु हुआ है।वहीं नक्सलियों ने जिन जगहों पर गड्ढे खोदे थे उनके आसपास बम लगा होने के बैनर पोस्टर चस्पा किए गए थे।जिसकी

तलाश में मौके पर बम निरोधक दस्ता भी एक्टिव है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही प्रदेश में कई जगह नक्सली वारदात बढ़ गई है।खासकर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नक्सली रोजाना उत्पात मचा रहे हैं।जिसके बाद नई सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए सख्ती की बात कह चुकी है।आपको बता दें कि नक्सलियों ने इससे पहले नारायणपुर में भी उत्पात मचाया था।जहां नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर भारत बंद का आह्वान किया था।

नक्सलियों ने बीजापुर में बस को आग के हवाले किया था । यात्री बस को आग के हवाले करने के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग निकले थे। पुलिस के मुताबिक नक्सली ने दहशत फैलाने के इरादे से 22 किलोमीटर के क्षेत्र में दो यात्री बसों को आग के हवाले कर दिया था। पहली घटना बीजापुर के तिम्मापुर इलाके में हुई जबकी दूसरी घटना बासागुड़ा थाना क्षेत्र के आवापल्ली में हुई। घटना के पहले बड़ी संख्या में नक्सली पहुंचे थे और यात्री बसों को रुकवाकर उसमें आग लगा दिया था।

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जब नक्सलियों ने बस को घेरा तब बस में ड्राइर और क्लीनर दोनो मौजूद थे। ड्राइवर और क्लीनर दोनो किसी तरह से मौके से जान बचाकर जंगलों के रास्ते भागकर थाने पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। इससे पहले माओवादियों ने बीजापुर के मद्देड़ में मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया था। बसों में आग लगाने और मोबाइल टावर को फूंकने की घटना से बीजापुर में दहशत का माहौल है। माओवादियों ने कल भारत बंद भी बुलाया है जिसे देखते हुए पूरे बस्तर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जवानों ने किए हैं।

नक्सलियों का कांकेर में भारत बंद का असर

कांकेर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के भारत बंद का असर दिखने लगा है। कांकेर के बड़गांव में व्यापारियों ने अपनी दुकानें सुबह से बंद रखी है। साथ ही भानुप्रतापपुर से पखांजुर और पखांजुर से गढ़चिरौली मार्ग पर यात्री वाहनों के पहिये थमे हुए है। जिससे यात्रियों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।

पूर्वी बिहार,झारखंड,उत्तर प्रदेश के संघर्षरत जनता पर सरकारी दमन के विरोध के साथ सूरजकुंड रणनीतिक योजना का विरोध करने की मांग को लेकर नक्सलियों ने भारत बंद का आह्वान किया था। जिसे लेकर सुरक्षाबलों ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है।

शुक्रवार को माओवादियों के बुलाए भारत बंद से एक दिन पहले ही नक्सलियों ने बस्तर में जमकर उत्पात मचाया। बीजापुर के तिम्मापुर इलाके में नक्सलियों ने कुशवाहा ट्रैवेल्स की बस को आग के हवाले कर दिया। यात्री बस में आग लगाने की खबर से जैसे ही इलाके में फैली लोग दहशत में आ गए। नक्सलियों ने जिस यात्री बस को आग के हवाले किया वो यात्री बस जगदलपुर से बासागुड़ा के लिए रवाना हुई थी। नक्सलियों के उत्पात को देखते हुए सभी यात्री बसों के मालिकों ने अपनी अपनी गाड़ियों को सुरक्षित जगह पर खड़ा दिया। माओवादियों के आगजनी की खबर से बसों में सफर करने वाले यात्री भी दहशत में हैं। हजारों की संख्या में बसों से बस्तर आने वाले और बस्तर से बाहर जाने वाले मुसाफिरों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है।

कांकेर में मोस्ट वांटेड नक्सली गिरफ्तार बड़ी वारदातों में थे शामिल

कांकेर। नक्सलियों के भारत बंद के बीच कांकेर पुलिस को नक्सल उन्मूलन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। कांकेर पुलिस ने दो जनमिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है। एक नक्सली ने बीएसएफ जवान की हत्या की थी तो दूसरे ने 3 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा था।

कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि जनमिलिशिया सदस्य रामसाय उईके को नारायणपुर जिला अंतर्गत मलमेटा के साप्ताहिक बाजार से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली परतापुर थाना अंतर्गत सक्रिय रूप से जनमिलिशिया सदस्य के रूप में काम कर रहा था। 14 दिसम्बर 2023 को ग्राम परतापुर सड़कटोला मंदिर टेकरी के पास आईईडी ब्लास्ट में शामिल रहना कबूल किया है। इस घटना में आर।एस।ओ। ड्यूटी में लगे बीएसएफ का एक प्रधान आरक्षक अखिलेश कुमार राय शहीद हो गया था।

दूसरा जनमिलिशिया सदस्य सुरेश कतलामी आलदंड के रहने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली थाना छोटेबेठिया अंतर्गत जनमिलिशिया सदस्य के रूप में काम कर रहा था। गिरफ्तार नक्सली पखांजुर के पीव्ही 92 चौक गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में नक्सली ने 30 अक्टूबर । 2023 को ग्राम मोरखण्डी के तीन ग्रामीणों मनोज कोवाची, कुल्लेराम कतलाम, दोगे कोवाची निवासी मोरखण्डी के अपहरण और हत्या करने में शामिल रहना कबूल किया है। दोनों नक्सली को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नक्सलियों ने जमकर मचाया उत्पात, बसों के पहिए थमे

जगदलपुर। नक्सली 16 से 22 दिसंबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाने का ऐलान के साथ 22 दिसंबर कों भारत बंद का आह्वान किया था, 22 दिसंबर से दो दिन पहले नक्सली अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में यात्री वाहनों में आगजनी, पेड़ काटकर एवं सडक काटकर मार्ग अवरूद्ध कर जमकर उत्पात मचाया है। जिसके बाद से नक्सल प्रभावित इलाकों में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री वाहन पूरी तरह से बंद कर दिये गये हैं। शुक्रवार को नक्सल प्रभावित सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जिलों में यात्री वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बस्तर संभाग में पड़ रहे कंपकपाती ठंड के चलते यात्रियों के सामने संकट उत्पन्न हो गया है। आज नक्सलियों के प्रतिरोध सप्ताह का अंतिम दिन है, इसके बाद ही यात्री वाहनों का पचिालन सामान्य होने की बात कही जा रही है।

उल्लेखनिय है कि नक्सली प्रतिरोध सप्ताह के अंतिम दो दिनों में नक्सलियों के सबसे आसान शिकार माने जाने वाले में से एक वाहनों में आगजनी करने को अंजाम देकर तथा मार्ग में गड्ढे खोदकर, बैनर पोस्टर लगाकर अपनी मौजूदगी का प्रभाव दिखाने में सफल रहे है। इसी कड़ी में नक्सली गुरूवार देर शाम को दुगईगुड़ा पास रॉयल ट्रेवल्स और कुशवाहा ट्रेवल्स यात्री बसों को आग के हवाले कर दिया। सुकमा जिले में तेलंगाना राज्य परिवहन की एक यात्री बस, दो ट्रक और एक मेटाडोर सहित चार वाहनों में आग लगा दी। बीजापुर जिले के ग्राम बेलचर के नजदीक एनएच में पेड़ काटकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया हैं। इसी तरह यहां से 6 किमी दूर ग्राम डोडरा के नजदीक नक्सलियों ने एक भाजपा नेता के वाहन सहित कई छोटी गाडियों में भी तोड़-फोड़ किया है। वहीं जगरगुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारगुड़ा के पास नक्सलियों ने एक पिकअप वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। अबूझमाड़ इलाके में भी नक्सलियों ने अलग-अलग इलाकों में पेड़ काटकर तथा सड़क खोदकर मार्ग को बंद कर दिया है, साथ ही बड़े पैमाने पर बैनर-पोस्टर लगाकर 22 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान जमकर उत्पात मचाया है, जिसके बाद से नक्सल प्रभावित इलाकों में यात्री वाहनों सहित सभी प्रकार की वाहन के पहियों में ब्रेक लग गया है।

आईईडी विस्फोट में शामिल नक्सली बाल संघम के 2 नाबालिक सदस्य पकड़ाए

दंतेवाड़ा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना मालेवाही, डीआरजी/बस्तर फाईटर्स दंतेवाड़ा एवं सीआरपीएफ 195 बटालियन डी कम्पनी मालेवाही का संयुक्त बल इन्द्रावती एरिया के नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर थाना मालेवाही के ग्राम बोदली, घोटिया एवं टेटम की ओर रवाना हुए थे।

अभियान के दौरान शुक्रवार की सुबह ग्राम बोदली के जंगल में 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने व छिपने लगे। जिसे पुलिस पार्टी के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गये दोनों संदिग्धों से पूछताछ करने पर पीडियाकोट आरपीसी में बाल संघम सदस्य के पद पर कार्य करना बताये साथ ही 2 दिसंबर को ग्राम बोदली नयापारा मेन रोड में आईईडी विस्फोट की घटना में शामिल होना व मौज़े पर रेकी करने आना बताये। विवेचना के दौरान दोनो संदिग्धों का नाबालिक होना पाया गया। थाना मालेवाही के अप. क्रं.-05/2023 धारा 341, 307 भादवि. 3,5 वि.प.अधि. 8(1) (3) (5) छ.ग.वि.जनसु.अधि. में दोनो विधि से संघर्षरत बालकों की प्रकरण में संलिप्तता, पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से किशोर न्याय बोर्ड जगदलपुर के समक्ष पेश किये जाने के लिए रवाना किया गया।

फर्जी ठेकेदार ने सरपंच से की लाखों की ठगी

गरियाबंद। शातिर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका निकाल है। पंचायत में चल रहे किसी भी निर्माण कार्य के बहाने फर्जी ठेकेदार का कॉल कर पंचायत में कार्यरत मजदूरों को भुगतान के बहाने ठगी का शिकार बना रहे हैं। यह ममला गरियाबंद जिले से आया है। जहां शातिर ठग ने सरपंच को फ्रॉड कॉल पर कहा जलजीवन मिशन का काम करने मजदूर गए हैं, जिनके राशन के लिए पैसे डाल रहा हूं। फर्जी ट्रांजेक्शन मैसेज के जरिए ज्यादा रकम जाना बता कर वापस 1।98 लाख रुपये ले लिया। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को एक ऑनलाइन ठगी का शिकार दहीगांव के सरपंच खगेश्वर नागेश हो गए हैं। उन्हें मोबाइल नंबर 9696896690 से कॉल आया, कॉल करने वाला अपने आप को जल जीवन मिशन का ठेकेदार बताया और कहा की उनके पंचायत के आश्रित ग्राम दबनई ने मिशन के तहत काम करने उनके मजदूर जा रहे हैं। उन्हीं के राशन खर्च के लिए 50 हजार पेमेंट डालना था। सरपंच ने पेमेंट रिसीव के लिए अपने बेटे का नंबर दिया। जिसमें ठग ने बैंक ट्रांजेक्शन के 3 फर्जी मेसेज डाला, दो मेसेज 49000 के थे, तीसरा 99000 के थे। मैसेज के आते ही ठग ने बेटे को नेटवर्क इशू के कारण ज्यादा पेमेंट डल जाने का हवाला देकर तीनो पेमेंट वापस मांगे। बेटे ने बगैर खाता पड़ताल के ठग के दिए गए 'फोन पे' नंबर 9628329182 पर 1।98 लाख रुपये डाल दिए। यह रकम कारोबार करने लोन पर लिया गया था। इस मामले में थाना प्रभारी गौतम गावड़े ने बताया कि शिकायत के आधार पर धारा 420 व 66 घ आईटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कांग्रेस ने बचाई कटघोरा नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी

कोरबा। कटघोरा नगर पालिका में बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने से कांग्रेसियों में खुशी का माहौल है। भारी गहमा गहमी के बीच वर्तमान कांग्रेस समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष रतन मित्तल ने चुनाव जीता। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने से बीजेपी पार्षदों को निराशा हाथ लगी है। वहीं कांग्रेस की फिर से नपा अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस पार्षदों ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर जीत की खुशी मनाई। कांग्रेसियों ने निर्वाचित अध्यक्ष मित्तल को बधाई भी दी। निर्वाचित अध्यक्ष रतन मित्तल ने कहा, यह जनता की जीत है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन बीजेपी अपना अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए।

बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 30 जून तक दाखिला

जगदलपुर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के तहत निजी अशासकीय, गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में निर्धन एवं कमजोर तबके के बच्चों का प्रवेश वर्ष 2024-2025 की कार्यवाही किये जाने हेतु समय सारणी घोषित की गई है। जिसके तहत स्कूल प्रोफाइल अपडेट के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 01 फरवरी से 24 फरवरी 2024 तक, छात्र पंजीयन आवेदन 01 मार्च से 15 अप्रैल 2024 तक, नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेज की जांच 18 अप्रैल से 17 मई 2024 तक, लॉटरी एवं आबंटन 20 मई से 30 मई 2024 तक और स्कूल दाखिला प्रक्रिया 01 जून से 30 जून 2024 तक की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वितीय चरण में नवीन स्कूल पंजीयन आवेदन की कार्यवाही के तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 15 जून से 30 जून 2024 तक, छात्र पंजीयन आवेदन 01 जुलाई से 08 जुलाई 2024 तक की जाएगी।

झूठा शपथ पत्र बनाने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बरगांव में कस्तूरबा गांधी आश्रम में फर्जी शिक्षाकर्मी वर्ग दो में पद पर पदस्थ कुमारी मंदोदरी वर्मा को पूर्व में गिरफ्तार किया गया है। वहीं शपथ पत्र में फर्जी हस्ताक्षर करने वाले आरोपी भाई संतोष वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है। नवागढ़ थाना प्रभारी कमलेश सेंडे ने बताया की नदराम वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराया था की कुमारी मंदोदरी वर्मा जोकि बीएड की फर्जी अंकसूची बनाकर कस्तूरबा गांधी आश्रम में शिक्षाकर्मी वर्ग दो के पद पर वर्ष 2008 से पदस्थ हैं। वहीं उसके भाई संतोष वर्मा ने फर्जी शपथ पत्र में हस्ताक्षर किया है। जांच पड़ताल में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद आरोपी मंदोदरी वर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। वहीं इस फर्जी दस्तावेज में संलिप्त आरोपी का भाई संतोष वर्मा भी शामिल था जिसने झूठे शपथ पत्र में हस्ताक्षर किया था जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को सरवानी बलौदा बाजार से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

धमतरी में बड़ा हादसा, शटरिंग गिरने से तीन मजदूर दबे

धमतरी। धमतरी से विशाखापत्तनम तक भारतमाला परियोजना के तहत हो रहे सडक निर्माण में एक बडा हादसा हो गया। शटरिंग गिरने से तीन मजदूर दब गए। इनमें से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर केरेगांव पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि भारतमाला परिजयोजना के तहत धमतरी से विशाखापत्तनम तक 6 लेन सडक का निर्माण हो रहा है। केरेगांव के पास पुल निर्माण के लिए शटरिंग की गई थी। वह अचानक ढह गई जिसके चलते वहीं नीचे काम कर रहे तीन मजदूर इसमे दब गए। आनन फानन में तीनो मजदूरो को निकाला गया, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि घायल दो मजदूरो को इलाज के लिए धमतरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक का शव जिला अस्पताल में रखा गया है। केरेगांव पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

एक शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव, रायपुर भेजी रिपोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट जेएन.1 की एंट्री हो चुकी है। यहां एक 49 साल का शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। देश में पांच सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों में जेएन.1 पाया जा रहा है। बीते एक सप्ताह में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए मरीजों के सभी सैंपल में नया वेरिएंट मिला है। जो 40 से अधिक देशों में संक्रमण बढ़ा रहा है। देश के 11 राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है। बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेश शुक्ला ने बताया कि अब तक 136 लोगों का परीक्षण किया गया है। जिसमें से एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज को बीते कुछ समय से खांसी और सर्दी थी। यह जांचने के लिए नमूना एम्स रायपुर भेजा जाएगा कि वेरिएंट नया है या पुराना। मरीज के विदेश यात्रा से वापस लौटने की बात कही जा रही है। मरीज शहर के तालापारा क्षेत्र का है। इन्साकॉग के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है।

हसदेव जंगल में फिर शुरू हुई पेड़ों की कटाई

■ कोल खदान का विरोध करने वाले हिरासत में

सरगुजा। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही हसदेव अरण्य क्षेत्र में एक बार फिर से पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन व वन विभाग की अनुमति के बाद गुरुवार से पीईकेबी 2 परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। वर्तमान में लगभग 93 हेक्टेयर भूमि में 9000 से ज्यादा पेड़ों के कटाई की योजना बनाई गई है। पिछली बार पेड़ों की कटाई को लेकर उपजे विवाद व विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इस बार प्रशासनिक महकमा पहले से ही अलर्ट मोड़ पर है और विरोध करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

राजस्थान राज्य विद्युत् वितरण कम्पनी को आबंटित व अडानी कंपनी द्वारा संचालित परसा ईस्ट केते बासेन 2 कोल परियोजना के लिए पेड़ों के कटाई की

अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है। पेड़ों की कटाई और कोयला उत्पादन की अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन की मदद से पहले दो बार पेड़ों की कटाई का काम शुरू किया गया था लेकिन दोनों ही बार ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण पेड़ों की कटाई बीच में ही रोकनी पड़ गई थी लेकिन अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक बार फिर से पेड़ों की कटाई का काम शुरू किया गया है।

हसदेव अरण्य क्षेत्र में आने वाले हरिहरपुर, साल्ही, घाटबर्रा, फतेहपुर, बासेन, परसा में पुलिस बल को तैनात किया गया और फिर पेड़ों की कटाई शुरू की गई। घाटबर्रा, पेंड्रामार जंगल में सुबह 10 बजे से पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई थी। इस दौरान जंगल के कक्ष क्रमांक 2003, 2004, 2005 और 2006 में चार अलग अलग टीमों द्वारा हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई।

हाल ही में भारत सरकार के कोल मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की बैठक लेकर पेड़ों की कटाई कराने के साथ ही जल्द से जल्द खदान से कोयला उत्पादन शुरू करने के निर्देश दिए थे। ओपन कास्ट माइंस से कोयला उत्पादन को लेकर सरकार से मिले निर्देश के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार ने नेतृत्व में जिला प्रशासन, वन विभाग की टीम उदयपुर क्षेत्र में पहुंची थी।पीईकेबी फेज 1 के खदानों से कोयला उत्पादन का कार्य किया जा रहा था जबकि ओपन कास्ट माइंस पीईकेबी 2 कोल परियोजना के लिए लगभग 21 सौ हेक्टयर जंगल में खनन व पेड़ों के कटाई की स्वीकृति साल 2011 में ही दी जा चुकी है। इस योजना के तहत हर साल लगभग 150 हेक्टेयर जंगल की कटाई कर उसमें से कोयला उत्पादन किया जाना है लेकिन विगत वर्ष दो बार कोयला पेड़ों की कटाई का विरोध किया गया। ऐसे में लगभग 41 हेक्टेयर जंगल में ही पेड़ों की कटाई हो पाई थी। पेड़ों की कटाई पूरी नहीं होने के कारण कोयला उत्पादन चार पांच महीनों से प्रभावित हो गया था इसीलिए वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा शासन के निर्देश पर पिछले बार के स्वीकृत 93 हेक्टेयर जंगल में ही पेड़ों की कटाई शुरू कराई गई है। 93 हेक्टेयर जंगल में 9 हजार से अधिक पेड़ काटे जाने की बात कही जा रही है।

किसानों के खाता होल्ड होने के बावजूद जारी किया राशि, नोडल अधिकारी निलंबित

जांजगीर-चांपा। जिला सहकारी बैंक जांजगीर के नोडल अधिकारी अश्वनी पाण्डेय पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि 145 किसानों के खाता में फर्जी तरीके से समर्थन मूल्य में धान बेचा गया था। जिला प्रशासन ने धान खरीदी में गड़बड़ी मिलने पर खाता पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद नोडल ने कलेक्टर के आदेश का अवहेलना करते हुए 61 लाख से अधिक राशि का अवैध तरीके से भुगतान कराया। कलेक्टर के आदेश पर जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के मुख्य कार्य पालन अधिकारी ने निलंबित किया है।

जानकारी के अनुसार, तहसील नवांगढ़ अन्तर्गत धान उपार्जन केंद्र तुलसी और किरीत में शासकीय भूमि का फर्जी पंजीयन कर अवैध बिक्री किये 145 कृषकों का होल्ड कर राशि आहरण भुगतान पर रोक लगाई गई थी। उक्त होल्ड और बोनस राशि को संबंधित किसानों को भुगतान किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तरीय जांच दल गठित कर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार होल्ड राशि रूपये 77 लाख 15 हजार 336 रूपये में से 61 लाख 62 हजार 888 रुपये अवैध आहरण कर भुगतान पाये जाने पर अश्वनी कुमार पाण्डेय नोडल अधिकारी के खिलाफ गड़बड़ी पाई गई। जिसके बाद निलंबित की कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टरों के साथ की वीसी

प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को दें सर्वोच्च प्राथमिकता

कानून-व्यवस्था और राजस्व मामलों पर दिए सख्त निर्देश जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा

- कानून व्यवस्था पर कलेक्टर , एसपी को दिए निर्देश
- प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज दिखना चाहिए
- जुआ-सट्टा, अवैध शराब की बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई
- मुख्यमंत्री राजस्व मामलों के निराकरण की देरी पर भी सख्त
- राजस्व प्रकरण निराकरण में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
- राज्य में कहीं से भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए
- राजस्व से जुड़े सभी काम तत्काल होने चाहिए : मुख्यमंत्री

प्रदेश में हो कानून का राजः साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों से पहली बार मुखातिब हुए। उन्होंने सभी कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए ताकि शीघ्र ही इनका निर्माण किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा। श्री साय ने राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण भी तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फौती, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन और नक्शा दुरूस्तीकरण जैसे कामों को लेकर जनता से किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बिना किसी लेन-देन के लोगों के काम तेजी से होने चाहिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में नालियों और गलियों की साफ-सफाई पर विशेष जोर देने को कहा। उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा तथा मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन होते ही 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने और 12 लाख किसानों को दो वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने आवास के लिए पात्र सभी लोगों की सूची तत्काल तैयार करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए। श्री साय ने आगामी 25 दिसम्बर को प्रदेश में मनाए जाने वाले सुशासन दिवस की तैयारी के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कलेक्टरों के साथ प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव और रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के संभावित लक्षण वाले लोगों के सैम्पल की जांच प्रतिदिन ज्यादा-ज्यादा से संख्या में करने को कहा। उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की जांच के लिए अस्पतालों में मॉक-ड्रिल भी करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में सभी कलेक्टरों से कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। शासन की हर योजना लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग जनता के हित में करें। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से रूके हुए कार्यों पर विशेष ध्यान दें। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आप लोग नई ऊर्जा और उत्साह से काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने वीसी में कहा कि सरकार गठन के शुरूआती आठ दिनों में ही राज्य में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शासन और प्रशासन को मिलकर इन फैसलों का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस के बाद 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस मनाया जाना है। वीर बाल दिवस के माध्यम से बच्चों में वीरता का भाव जगेगा। उन्होंने कलेक्टरों को इसकी तैयारी के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव श्री अय्याज फकीर तम्बोली, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री जयप्रकाश मौर्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोस्कर विलास संदिपान, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा और आईडीएसपी के नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र गहवई भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में छग पुलिस के सितलेश ने हासिल किया कांस्य पदक

रायपुर। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में 10 वी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 21 दिसंबर तक हुआ। जिसमे छग पुलिस के सितलेश पटेल जो कि राजनांदगांव पुलिस में पदस्थ है ने 76 किलो वजन वर्ग में इंकलाईन बेंच और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेलते हुए 500 किलो वजन उठाकर कास्य पदक हासिल किया। छग वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन (एम) के अध्यक्ष मानिक ताम्रकार ने बताया कि प्रतियोगिता में विश्व के अनेक देशों के करीब 300 से अधिक खिलाड़ी आए थे। सितलेश पटेल ने इसके पूर्व नेपाल में भी मेडल ले चुके है। उनके इस उपलब्धि पर बॉडी टेक राजनांदगांव के मालिक अमित अजमानी, रविंद्र मिश्रा, शिव मोहन शुक्ला, अध्यक्ष हरि वल्लभ अग्रवाल, हेमंत परमाले सीनियर उपाध्यक्ष, कुंदन सिंह ठाकुर,पोषण बांधे, दुर्गेश साहू, पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन छग के महासचिव ऊदल वाल्मीकि, अध्यक्ष लखपति सिंदूर ने उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दिए।

सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख सहायता

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बालोद जिले के मरकाटोला घाट में आज हुए यात्री बस हादसे में मृतक तीन यात्रियों के परिजनों को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घायलों को समुचित उपचार मुहैया कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दुर्घटना में दिवंगतों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि बालोद जिले में सड़क हादसे में तीन लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुःखद है। उन्होंने इस दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष के नाम जमीन की रजिस्ट्री को घोषित किया शून्य

रायपुर। चर्चित मोवा जमीन विवाद मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला दिया है. जिसमें युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष आसिफ मेमन ने नूर बेगम की मोवा स्तिथ जमीन की अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई थी, इसे न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है.

कांग्रेस नेता आसिफ मेमन ने नूर बेगम से इस जमीन का सौदा 3 करोड़ 9 लाख 76 हजार में किया और इसके एवज में रजिस्ट्री करवाते समय 7 चेक दिया था. जिसमें एक भी चेक क्लियर नहीं हुआ. इसके बाद ये पूरा मामला नूर बेगम न्यायालय लेकर गई तो न्यायालय ने आज उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया है.

बता दें कि इसी मामले में न्यायालय ने कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस को एफआईआर करने का आदेश भी दिया है. सिविल लाइन्स पुलिस के द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज कर लिया गया है. उसके बाद से कांग्रेस नेता आसिफ मेमन फरार है. उसके खिलाफ न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है. इधर कांग्रेस नेता से अपनी जान का खतरा बताते हुए नूर बेगम ने पुलिस से लिखित शिकायत भी कर चुकी है.

मनोज पिंगुआ को मिला माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार

रायपुर। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज पिंगुआ को माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है. इसके अलावा वर्ष 2021 बैच के तीन परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में फेस दो प्रशिक्षण के बाद राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के नवीन पदस्थापना दी गई है. मनोज पिंगुआ पहले ही वन विभाग के प्रमुख सचिव और गृह एवं जेल विभाग के प्रमुख सचिव के अलावा नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के प्रमुख आवासीय आयुक्त का दायित्व संभाल रहे हैं.

साय कैबिनेट विस्तार पर भूपेश बघेल की चुटकी बहुत सारे नेताओं के सूट धरे के धरे रह गए

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट का शुक्रवार को विस्तार हो गया। बीजेपी के कुल 9 विधायकों ने शपथ ली है। जिसमें पुराने चेहरों के साथ नए चेहरे भी शामिल हैं। कई बड़े विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले तंज कसा है। भूपेश के वार पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय कैबिनेट विस्तार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के सूट धरे के धरे रह गए। कई नेताओं ने नए नए सूट सिलाए थे। लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और उनके नए नए सिलाए गए सूट धरे रह गए। सभी नए मंत्रियों को भूपेश बघेल ने बधाई दी है और साय सरकार के कामकाज की सुस्त रफ्तार पर निशाना साधा है।

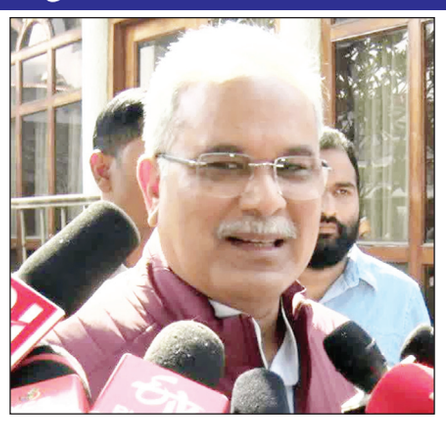

भूपेश बघेल ने कहा मैं सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं। अभी यह सभी मंत्री बने हैं,उन्हें विभाग मिलेगा। उसके बाद काम करेंगे तब कहा जा सकता है कि इन्होंने क्या काम किया,अभी सिर्फ सभी मंत्रियों को बधाई दूंगा।

भूपेश बघेल ने बीजेपी की तरफ से नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बार जीते विधायक राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो यहां यदि मंत्री बने हैं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हैं। वहीं कई वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। जो सूट सिला कर मंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनकी कवायद धरी की धरी रह गई।

भूपेश बघेल के बयान पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का सूट उतर गया है। इसलिए वह सबके सूट की बात कर रहे हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों को लेकर चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नवगठित विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रीमंडल का विस्तार शुक्रवार को आखिर हो ही गया। मुख्यमंत्री सहित दो उपमुख्यमंत्री के बाद अब नौ केबिनेट मंत्रियों ने भी अब शपथ ले ली है। राजभवन में राज्यपाल हरिचंद्रन ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी मंत्री शपथ ग्रहण के बाद राजभवन से सीधे मंत्रालय पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय पहले से वहां मौजूद थे।

उन्होने सभी नए मंत्रियों का मंत्रालय में स्वागत किया। केबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब चर्चा पोर्टफोलियों की हो रही है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा इसे लेकर अभी से कयास लगाए जा रहे है। मंत्रीमंडल में नए और पुराने विधायकों दोनों को ही पर्याप्त स्थान मिला है। संभावना जताई जा रही है कि महत्वपूर्ण और बड़े मंत्रालय जैसे कि लोक निर्माण, गृह, वन, पर्यटन, नगरीय निकाय, उच्च शिक्षा आदि वरिष्ठ लोगों को दिया जा सकता है। हालांकि चर्चा यह भी है कि नए लोगों को महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह चौका भी सकती है। केबिनेट में किसे कौन सा विभाग देना है यह तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार माना जाता है। एक-दो दिन में स्थिति स्पष्ट होने के आसार नजर आ रहे है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिल रहा है।

भारतीय किसान संघ ने किया मुख्यमंत्री साय का आत्मीय अभिनंदन

- **प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी का आदेश जारी होने से खुशी से झूम उठे किसान**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी होने से छत्तीसगढ़ के किसान खुशी से झूम उठे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर अमल शुरू होने पर भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ ने राज्य अतिथि गृह पहुना में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आत्मीय अभिनंदन करते हुए कहा कि किसानों को राज्य में किसान हितैषी सरकार के गठन की प्रतीक्षा थी। किसानों की सरकार के मुखिया श्री विष्णुदेव साय ने बहुत ही अल्प समय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की बड़ी गारंटियां पूरी कर दी हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गठित छत्तीसगढ़ राज्य की नई सरकार किसानों के भरोसे का सम्मान कर रही है।

इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री नवीन शेष, प्रदेश कार्यालय मंत्री दुर्गा पाल, महानगर प्रमुख विष्णु वर्मा, महानगर कार्यकारिणी सदस्य डॉ. बोधन साहू सहित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का अभिनंदन किया और राज्य की किसानों की ओर से उनका आभार जताया।

राज्य के किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से अब प्रति एकड़ के मान से 21 क्विंटल धान 3100 रूपये क्विंटल की दर पर विक्रय से 23,355 रूपए ज्यादा मिलेंगे। इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ रुपए की धान खरीदी होगी। धान बेच चुके किसानों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा। 25 दिसम्बर राष्ट्रीय सुशासन दिवस पर किसानों को 3716 करोड़ रुपए बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों से मिली राशि में से छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि राज्य को हस्तांतरित करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह जनता से किए गए हमारे वादों को पूरा करने के हमारे प्रयासों को बल प्रदान करेगा। गौरतलब है कि आगामी त्यौहारों और नये वर्ष को देखते हुए केन्द्र द्वारा छत्तीसगढ़ को 2485.79 करोड़ रूपए की किश्त जारी की गई है। यह किश्त केन्द्र द्वारा 11 दिसम्बर 2023 को जारी की गई किश्त के अतिरिक्त है। केन्द्र सरकार से मिली इस राशि से राज्य सरकार को समाज कल्याण की योजनाओं तथा अधोसंरचना विकास योजनाओं के वित्तीय पोषण में मजबूती मिलेगी।

तीन पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर व कांकेर में 1-1 कोरोना के मरीज मिले है जो कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित है। इनमें एक रायपुर एम्स की नर्स, बिलासपुर का कारोबारी शामिल हैं। वहीं कांकेर के मरीज के संबंध में जानकारी नहीं मिली है। बताया गया है कि बिलासपुर का कारोबारी सिंगापुर से मुंबई होकर पहले रायपुर से बिलासपुर पहुंचा है। इन तीनों को आईसोलेशन में रखा गया है। नये मरीज मिलने के बाद से जिला प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो गया है और लोगों से भीड़ वाले इलाकों में मास्क और दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्दी, खांसी के साथ वायरल फीवर व जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है, उनकी जांच कराई जाएगी। इससे पॉजीटिव केस की संख्या बढने की आशंका है। शासन ने सभी जिलों के कलेक्टर को पहले ही अलर्ट रहने को कहा है। आंबेडकर अस्पताल समेत बड़े अस्पतालों को तैयारी रखने को भी कहा गया है। फिलहाल आंबेडकर अस्पताल के आईसीयू में 16 बेड और पांच वेंटीलेटर रिजर्व रखा गया है।

हालांकि राज्य में कोविड नियंत्रण में है अनावश्यक घबराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु सावधानी बरतना आवश्यक है। पूर्व में जारी कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों तथा कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे मास्क लगाना, साबुन से हाथ धोना, सेनेटाईजर का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, संभावित लक्षण वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखना इत्यादि नियमों का पालन करें। सर्दी, खांसी, बुखार या स्वांस में तकलीफ होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पतालों में उपस्थित होकर जांच एवं उपचार करानेआग्रह किया है।

वर्षा झा आईबी ग्रुप में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट

रायपुर। टाटा स्टील व ऐस्सार (वर्तमान मे आरसेलर मित्तल निपॉन स्टील) कंपनी में सीएसआर के प्रमुख पद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली वर्षा झा राजनांदगांव स्थित कार्पोरेट घराना आईबी ग्रुप में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, कॉरपोरेट रिलेशंस एवं कंप्लायंस का पद सम्हालेंगी।

विगत कुछ वर्षों से निजी कारणों से नियमित कार्पोरेट जीवन से 3 साल का कैरियर ब्रेक लेने के बाद श्रीमती वर्षा झा फिर की फिर से कार्पोरेट सेक्टर में वापसी हुई है राजनांदगांव के कार्पोरेट घराना आईबी ग्रुप उन्हें कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, कॉरपोरेट रिलेशंस एवं कंप्लायंस के रूप में नियुक्त किया है।वे रायपुर में रहकर परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार ट्रैवल करेंगी। वर्षा झा ने लगभग डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ मे कार्य करने वाली दो प्रमुख कंपनियों टाटा स्टील व ऐस्सार (वर्तमान मे आरसेलर मित्तल निपॉन स्टील) के लिए आम आदमी के बीच सकारात्मक माहौल बनाने मे सफलता हासिल की थीं।

नगर निगम ने 2 लाख 80 हजार वर्गफीट जमीन को किया कब्जा मुक्त

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की ओर से अवैध रूप से संचालित दुकानों और सड़क पर यातायात बाधित करने वाले ठेलों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वहां दोबारा कब्जा ना हो जाए इसे सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम के अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय ने बताया कि, व्यस्ततम बाजार और मार्गों पर जहां बाजार और व्यवसायिक गतिविधियों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। ऐसे 18 स्थानों पर चूना मार्किंग की गई है। इसके बाहर किसी प्रकार का सामान रखने या अवैध रूप से पार्किंग की जाएगी तो सामान या वाहन को यातायात विभाग और निगम की ओर से जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

विनोद पाण्डेय ने बताया कि, अभी तक अवैध रूप से संचालित दुकानों और सड़कों पर यातायात बाधित करने वाले ठेलों को हटाते हुए लगभग 2 लाख 80 हजार वर्गफीट सड़क और जमीन को कब्जा मुक्त किया जा चुका है। साथ ही समस्त जोन कमिश्नरों को इन कब्जा मुक्त क्षेत्र में दोबारा कब्जा ना हो इसके लिए लगातार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)
ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल- https://eproc.cgstate.gov.in

(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 149722/निविदा सूचना क्र. 23/व.ले.लि./2023-24 **दि. 19.12.2023**

निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 09.01.2024 17.30 तक ऑन लाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है -

कार्य का नाम- बस्तर जिले के विकासखंड-बस्तर की कोसारटेडा मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना के मुख्य बांध की रिसेक्शनिंग कार्य एवं टरफिंग कार्य, पिचिंग सुधार एवं उन्नयन कार्य।

अनुमानित लागत- रु. 325.42 लाख
(एस.ओ.आर. दिनांक 01.08.2010 से प्रचलित (यथा संशोधित दिनांक 22.08.2022 तक))

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 26.12.2023 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते है।

नोट- निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर
कृते मुख्य अभियंता महानदी परियोजना
जल संसाधन विभाग, रायपुर छग

जी-06551

गतिरोध एवं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना दुर्भाग्यपूर्ण

ललित गर्ग

लोकसभा एवं राज्यसभा में सत्तापक्ष या विपक्ष का अनुचित एवं अलोकतांत्रिक व्यवहार न केवल अशोभनीय, अनुचित एवं मर्यादाहीन है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आदर्श परम्पराओं को धुंधलाने वाला है। शीतकालीन सत्र से लोकसभा के अब तक 95 एवं राज्यसभा के 46 कुल 141 सांसदों को सस्पेंड किए जाने के बाद विपक्षी सांसद संसद परिसर में धरना दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, निश्चित ही इस तरह का अपमानजनक एवं अशालीन व्यवहार भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने की चिन्ताजनक घटना है। उपराष्ट्रपति सर्वोच्च एवं सम्मानजनक पद है, इसकी गरिमा को आहत करना एवं उस पर आंच आने का अर्थ है राष्ट्र की अस्मिता एवं अस्तित्व को धुंधलाने की कुचेष्टा। तभी उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह हास्यास्पद और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मेरी मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं. लेकिन मैं कुर्सी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस कुर्सी की गरिमा बरकरार रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जाति, मेरी पृष्ठभूमि, इस कुर्सी का अपमान किया गया है। यहां बात सिर्फ लोकतंत्र के अपमान की भी नहीं है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिस तरह मिमिक्री कर उनका अपमान करने और हमारे संवैधानिक सर्वोच्च संस्थानों पर राजनीतिक हमले किये जाने का जो सिलसिला चला है वह एक तरह से भारत की छवि पर हमला है। इतने अधिक सांसदों का निलम्बन एवं उपराष्ट्रपति का अपमान लोकतांत्रिक इतिहास में इन्हें दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के रूप में देखा जाएगा। यह विपक्षी दलों की बौखलाहट ही है कि अपनी सरकती राजनीतिक जमीन को बचाने की जुगत में वे जायज-नाजायज सभी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भूलकर की उनकी भी कुछ मर्यादाएं एवं लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। यही विपक्ष कभी राष्ट्रपति तो कभी उपराष्ट्रपति, तो कभी प्रधानमंत्री के लिये अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो तानाशाह, हिटलर, नीच, मौत का सौदागर या कई अन्य अपमानजनक शब्द उपयोग किये हैं। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिस तरह अपमान किया गया उसने सार्वजनिक जीवन में मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। लोकतंत्र में असहमति एवं आलोचना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है और इसे उसी रूप में लेने की जरूरत है, लेकिन हठधर्मिता, विध्वंसात्मक नीति एवं मिमिक्री करने जैसी घटनाओं से लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोक राज्य, स्वराज्य, सुराज्य, रामराज्य का सुनहरा स्वप्न ऐसे अलोकतांत्रिक विपक्ष की नींव पर कैसे साकार होगा? यहां तो सभी दल अपना-अपना साम्राज्य खड़ा करने में लगे हैं। हालांकि विपक्षी दलों के तमाम अलोकतांत्रिक विरोध एवं उच्छृंखल रवैये ने निराशा का ही वातावरण बनाया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के पीछे मूलतः पिछले सप्ताह संसद की सुरक्षा में हुई चूक है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि यह गंभीर मसला है। सवाल सिर्फ यह है कि आखिर इस गंभीर मसले पर सदन के अंदर चर्चा की कोई राह दोनों पक्ष क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्यों विपक्षी दल इस बात पर अड़े हैं कि कानून व्यवस्था से जुड़े इस गंभीर मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, वहीं सरकार का कहना है कि संसद के अंदर की सुरक्षा स्पीकर की जिम्मेदारी होती है और इसलिए इस पर गृह मंत्री का बयान देना उचित नहीं होगा। लोकतंत्रीय पद्धति में किसी भी विचार, कार्य, निर्णय और जीवनशैली की आलोचना पर प्रतिबंध नहीं है। किन्तु आलोचक का यह कर्तव्य है कि वह पूर्व पक्ष को सही रूप में समझकर ही उसे अपनी आलोचना की छेनी से तराशे। किसी भी तथ्य को गलत रूप में प्रस्तुत कर उसकी आक्षेपात्मक आलोचना करना उचित नहीं है। जिन दलों, लोगों एवं विचारधाराओं का उद्देश्य ही निन्दा करने का हो, उनकी समझ सही कैसे हो?

इंडिया को स्वीकार नहीं राहुल का नेतृत्व

डॉ. आशीष वशिष्ठ

इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की चौथी बैठक दिल्ली में संपन्न हो गई। इस बैठक से उम्मीद थी कि गठबंधन अपना संयोजक या फिर प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई निर्णय ले सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। छह महीने में चार बैठकें करने बावजूद गठबंधन के दल साथ चलने, बीजेपी को हराने की हवा हवाई बातों से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। लेकिन इस बैठक में एक खास बात हुई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नाम का प्रस्ताव दिया। ममता का समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। हालांकि इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से खरगे का नाम आगे करके राहुल गांधी के नेतृत्व को खारिज कर दिया। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता समझते हुए खरगे ने कहा, पहले जीतें, फिर देखेंगे। इस मसले पर भले ही कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ममता और केजरीवाल ने राहुल की पीएम पद की दावेदारी को तो डाउन कर दिया।

बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की नीयत से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के गठन के लिए भागदौड़ की थी। नीतीश के प्रयासों के चलते ही बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद बेंगलुरु और मुंबई में दूसरी और तीसरी बैठक हुई। लगभग छह महीने में गठबंधन की चार बैठकें हुई। पहली बैठक से ही कांग्रेस अपने को ऐसे पेश कर रही थी कि, विपक्षी दल उसके प्रयासों से एकजुट हुए हैं। कांग्रेस ने हर बैठक में अपना हाथ और एजेंडा ऊपर रखा। कांग्रेस ने ऐसे प्रोजेक्ट किया कि इस गठबंधन को लीड करेगी और राहुल गांधी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। गठबंधन में शामिल कई दल राहुल गांधी के चेहरे और नाम पर सहमत नहीं थे। वो स्वयं को प्रधानमंत्री पद का सशक्त दावेदार समझते हैं।

कर्नाटक में शानदार जीत के बाद कांग्रेस का उत्साह सातवें आसमान पर था। 13 मई को कर्नाटक चुनाव नतीजों के ठीक एक महीना दस दिन बाद यानी 23 जून को विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक हुई। पहली बैठक में ही संयोजक, सीट शेयरिंग आदि मुद्दों पर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। विपक्षी पार्टियों के नेताओं की दूसरी बैठक जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी जहां गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन होगा, इस बात का ऐलान किया गया था। गठबंधन की तीसरी बैठक शिवसेना की मेजबानी में इस साल 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी। इस बैठक में गठबंधन की कोआर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था। कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी एक बैठक हुई थी। हालांकि, वह बैठक पांच राज्यों के चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले हुई थी।

इन तीन बैठकों में कांग्रेस जानबूझकर सीट शेयरिंग और संयोजक के नाम के अहम मुद्दे का टालती रही। कांग्रेस की मंशा यह थी कि पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव के बाद इन मसलों पर बात की जाएगी। असल में कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि कर्नाटक की भारी जीत और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उसके पक्ष में माहौल बना हुआ है, और वो इन राज्यों में शानदार जीत हासिल करेगी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उसका पलड़ा भारी होगा और वो अपने शर्तों के हिसाब से गठबंधन में शामिल दलों से तमाम मुद्दों पर तोल-मोल कर सकेगी। लेकिन कांग्रेस की चालाकी, रणनीति और हथकंडे फेल साबित हुए। और हिंदी पट्टी के तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से उसका सफाया हो गया। तेलंगाना में कांग्रेस को जीत तो मिली लेकिन तीन राज्यों की हार ने इस जीत का मजा किरकिरा कर दिया।

बीती 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई। उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडी अलायंस की बैठक की चौथी बैठक की घोषणा की। लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार ने कोई न कोई बहाना लगाकर बैठक में आने से इंकार कर दिया। असल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकदल में सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी हुई थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच शर्मनाक बयानबाजी खूब चर्चा में रही थी। कांग्रेस के इस व्यवहार से घटक दलों में रोष व्याप्त था। इसलिये 6 दिसंबर की बैठक को कांग्रेस को टालना पड़ा था।

विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भी सातवें आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरी। चुनाव नतीजों के बाद से ही उसके तेवर ढीले हैं। अब वो घटक दलों के साथ सहयोग और साथ चलने की कसमें खा रही है, लेकिन उसके रवैये से घटक दल चौकन्ने हैं। वो कांग्रेस के साथ चलना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों के आधार पर। चूंकि गठबंधन में शामिल हर दल का नेता स्वयं को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानता है, ऐसे में संयोजक और प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है।

खरगे के नाम का समर्थन करने का सीधा मतलब है राहुल के नाम और चेहरे को खारिज करना। कांग्रेस भी सारी कहानी को बखूबी समझ रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उसमें उतना दम नहीं बचा कि वो गठबंधन में शामिल दलों पर प्रेशर बना सके। चूंकि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार ही है तो ऐसे में गठबंधन के दलों ने खरगे का नाम का प्रस्ताव करके सीधेतौर पर गांधी परिवार को ही खारिज किया है। रही बात सीट शेयरिंग की तो वो बड़ा पेचीदा मसला है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में क्रमशः 80, 40, 42, 13 और 7 कुल मिलाकर 182 संसदीय सीटें आती हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव है। सपा और तृणमूल कांग्रेस अपने राज्यों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं हैं। क्षेत्रीय दल अपने प्रभाव क्षेत्र में किसी दूसरे दल पांव पसारने का मौका नहीं देना चाहते हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में मुस्लिम वोटरों के कांग्रेस के प्रति झुकाव को देखते हुए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव काफी चौकन्ने हो गए हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन की चौथी बैठक में राहुल गांधी को लेकर इंडिया गठबंधन की असहजता अब खुलकर सामने आने लगी है। इंडिया गठबंधन के भीतर यह बात बेहद चर्चा में है कि राहुल गांधी की वजह से मुद्दों में भटकाव होता है और बीजेपी को फायदा पहुंचता है। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता को मुफ्त योजनाओं का लालच दिया, जाति जनगणना का वादा किया, अदानी का मुद्दा उठाया, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, लेकिन हिंदी पट्टी के जिन तीन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर थी, वहां नतीजे उसके पक्ष में नहीं गये। जनता ने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया। जनता को कांग्रेस के वादों से ज्यादा पीएम मोदी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा जताया। पिछले दो दशकों के राजनीतिक करियर में राहुल गांधी के बायोडाटा में सफलता से ज्यादा असफलता की कहानियां दर्ज हैं। अधिकांष देशवासी राहुल को गंभीर और सकारात्मक सोच वाला नेता नहीं मानते। नतीजतन प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने कमजोर उम्मीदवार दिखाई देते हैं। शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और इंडी अलायंस में शामिल लगभग हर नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। चूंकि कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल किसी दल की अपने बलबूते बीजेपी से मुकाबला करने की ताकत नहीं है। इसलिए मजबूरी में ये सभी दल एक बैनर तले इकट्ठे हुए हैं। खरगे के बयान के बाद यह तो तय हो ही गया है कि गठबंधन किसी का नाम पीएम के तौर पर घोषित नहीं करेगा। मतलब गठबंधन के सभी दलों के नेता लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान तक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामण्युपनिषद् (भाग-19)

गतांक से आगे...

योग का अभ्यास करने के लिए एकान्त में बद्धपद्मासन लगाकर बैठे और शिवस्वरूप गुरु को नमस्कार करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए।

जिन नव द्वारों से वायु का गमनागमन होता है, उनका निरोध करके वायु को रोके और अपान को अनि से मिलाकर ऊर्ध्वगामी बनाकर शक्तिचालिनी मुद्रा द्वारा कुण्डलिनी मार्ग से दृढ़तापूर्वक ऊपर मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करे। जब तक यह स्थिर रहे, तब तक वह (अन्य) महापुरुष की संगति नहीं चाहता अर्थात् वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। संसार सागर से मुक्ति के लिए यह प्राणायाम महासेतु के सदृश है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाले अग्नि की तरह है, ऐसा योगियों द्वारा प्रायः कहा जाता है।

योग के आसनों से (शारीरिक) रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता है तथा प्रत्याहार करने से मानसरोग (विकार) समाप्त होते हैं। योग की धारणाशक्ति द्वारा योगी का मन धैर्यवान् बनता है, समाधि से जीव के शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा मुक्ति मिल जाती है। बारह बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है तथा बारह बार इसी तरह प्रत्याहार करने से शुभफलदात्री धारणा की सिद्धि होती है। इसी प्रकार धारणा की द्वादश आवृत्ति पर ध्यान बनता है तथा द्वादश बार ध्यान होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा योग के विशारदों का मत है।

समाधि की स्थिति में साधक परमप्रकाशरूप अनन्त विश्वतोमुख अर्थात् सर्वत्र समभाव प्राप्त कर लेता है, इस स्थिति को प्राप्त होने पर न तो कुछ करना शेष रहता है, न किये हुए कर्म मनुष्य को बन्धन में डालते हैं, इससे आवागमन से छुटकारा मिल जाता है।

क्रमशः ...

राष्ट्रीय किसान दिवस

रेनू तिवारी

हर साल भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान देश की अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति हैं और सम्मानित होने के पात्र हैं। यह दिन भारत के पांचवें प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म का भी जश्न मनाता है, जिन्होंने सरकार में अपनी जगह हासिल करने से पहले एक किसान के रूप में शुरुआत की थी। इस दिन का उद्देश्य किसानों के महत्व और राष्ट्र के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके बहुमूल्य योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

चौधरी चरण सिंह इस बात का एक उल्लेखनीय प्रमाण हैं कि विनम्र शुरुआत और सादा जीवन जीने के बावजूद कोई भी व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। इस महान व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित देश है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और भारत के नागरिक देश के विकास को बनाए रखने के लिए किसानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ऐसा होता है कि भारतीय इतिहास के महान नेताओं में से एक चौधरी चरण सिंह स्वयं उत्तर प्रदेश के एक छोटे किसान परिवार से थे। सिंह आगे चलकर किसानों के सम्मान की मिसाल कायम करते हुए भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने।

आजादी से पहले से आजादी के बाद तक, चौधरी चरण सिंह ने किसानों के सुधारों के लिए विभिन्न बिलों की वकालत और पारित करके भारत के कृषि क्षेत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता पार्टी के निधन के बाद प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई की सीट संभालते हुए, सिंह का कार्यकाल 1979 से 1980 तक था। प्रधान मंत्री के रूप में अपने छोटे समय के दौरान, सिंह ने भारतीय किसानों के कल्याण और बेहतरी के लिए प्रयास किया। किसानों की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं।

चौधरी चरण सिंह के अनुकरणीय कार्य और किसान से राज्य प्रमुख बनने तक की यात्रा के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2001 में सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर देश भर में हर साल कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों का किसान समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और उन्हें अपनी आकांक्षाओं और मांगों को उठाने के लिए मंच प्रदान करता है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को उनके उत्पादन को अधिकतम करने में सहायता करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और विज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। सरकार विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके किसानों का समर्थन भी करती है जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार आवश्यक

अनिल त्रिगुणायत

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो या इस विश्व संस्था के अन्य घटक हों, जैसे विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूनेस्को, मानवाधिकार परिषद, यानी वैश्विक शासन और वित्तीय प्रबंधन के जो भी औजार हैं, इनमें बड़े सुधारों की दरकार है। इस आवश्यकता को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर से रेखांकित किया है। जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि सात-आठ दशक पहले की परिस्थितियां कुछ और थीं। उस दौर की तुलना में आज विश्व व्यवस्था में बहुत बदलाव हो चुका है और वह बदलाव संयुक्त राष्ट्र में परिलक्षित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं स्थायित्व को सुनिश्चित करना था ताकि महायुद्ध जैसी भयावह परिस्थितियां फिर न उत्पन्न हो सकें। उल्लेखनीय है कि पहले विश्व युद्ध के बाद बना राष्ट्र संघ विफल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय पांच देशों, जो द्वितीय महायुद्ध में विजयी हुए थे, ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में किसी भी निर्णय के निषेध का विशेषाधिकार हासिल कर लिया। उस समय उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता था।

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख मंच है, जिसमें वर्तमान समय में 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जबकि पांच देशों- अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस- की सदस्यता स्थायी होती है। वीटो अधिकार प्राप्त इन पांच देशों को जब भी लगता है कि कोई प्रस्ताव उनके भू-राजनीतिक हितों के अनुरूप नहीं है, तो वे उसका निषेध कर देते हैं और वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। कई बार इनका रवैया व्यापक वैश्विक हित के विरुद्ध होता है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान द्वारा संरक्षित आतंकियों और आतंकी समूहों पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदी के अनेक प्रस्तावों को चीन ने

तकनीकी या प्रक्रियागत बहानों से बाधित किया था। मेरी राय है कि वैश्विक शासन में जो सबसे प्रमुख अवरोध है, वह ये पांच देश ही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इस्राइल-हमास संघर्ष से संबंधित प्रस्तावों को अमेरिका लगातार वीटो कर रहा है। इसी प्रकार रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़े प्रस्तावों पर चीन या रूस वीटो कर देते हैं। जिन देशों या क्षेत्रों में इन पांच देशों के भू-राजनीतिक हित हैं, उनके बारे में जब प्रस्ताव आते हैं, तो इन देशों का यही रवैया होता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने उचित ही इस समूह को ओल्ड क्लब की संज्ञा दी है, जो नये सदस्यों को नहीं आने देना चाहते हैं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। उनके ऐसे पैंतरों का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है।

भारत बहुत पहले से सुरक्षा परिषद और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में सुधार की मांग करता आया है। जितने भी विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय समूह हैं, भारत उनका संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की भावना और निर्णयों को भारत ने हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा है तथा वैश्विक संस्थाओं को बेहतर और बहुपक्षीय बनाने में हर संभव योगदान दिया है। फिर भी 'ओल्ड क्लब' के पांच स्थायी सदस्य 21वीं सदी के लगभग एक चौथाई हिस्से के बीत जाने के बाद भी अभी 20वीं सदी की मानसिकता से संचालित हो रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसकी अर्थव्यवस्था शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में है तथा उसकी गिनती सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में होती है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान लगभग 16 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भारत हमेशा से सबसे अधिक योगदान करने वाले देशों में रहा है। स्थायी सदस्यता के उसके दावे के ठोस आधार हैं। यह सदस्यता पहले ही मिल जानी चाहिए थी। अनेक स्थायी सदस्य देश बयान तो देते रहते हैं कि भारत को शामिल किया जाना चाहिए, पर वे सुधार के लिए गंभीर नहीं हैं। उन्हें पता है कि भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए चीन सहमत नहीं होगा, तो वे बयान देकर निकल जाते हैं।

यदि दुनिया की वर्तमान और भावी समस्याओं का ठोस समाधान निकालना है और युद्धों आदि को रोकना है, तो उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को स्थान देना होगा। साथ ही, महादेशीय प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि लगभग डेढ़ दशक से संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए प्रयास हो रहे हैं, पर मामला वहीं का वहीं है। इस संबंध में एक समूह का गठन भी हो चुका है। अगले वर्ष संयुक्त राष्ट्र का विशेष सम्मेलन इसी मुद्दे पर आयोजित होने वाला है। लेकिन स्थायी सदस्यों के रवैये को देखते हुए सुधार की बड़ी उम्मीद नहीं दिखती है। भारत के साथ-साथ जापान, ब्राजील और जर्मनी स्थायी सदस्यता के सबसे बड़े दावेदार हैं। जापान एशिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी तरह ब्राजील लातिनी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के साथ अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना भी सुधार का अहम पहलू है। जी-20 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकी संघ को सदस्यता मिली है। अफ्रीका सबसे बड़ा महादेश है। उसके समुचित प्रतिनिधित्व के लिए दो सदस्यों को लाने का प्रस्ताव है। ये देश कौन होंगे, यह निर्णय अफ्रीकी देश करेंगे।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव बयान देते रहते हैं, अपील करते रहते हैं, पर कोई नहीं सुनता। दुनिया में कई जगहों पर हिंसा और अस्थिरता है, पर यह विश्व संस्था कारगर हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है। आप राजनीतिक हल निकालने या शांति स्थापित करने की बात तो छोड़ दें, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं समुचित रूप से मानवीय मदद और राहत के कार्यों को भी ठीक से नहीं कर पास रही हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि पांच स्थायी सदस्यों की प्राथमिकता में संयुक्त राष्ट्र और उसकी भूमिका नहीं, बल्कि उनके अपने हित हैं। ऐसे में इस संस्था के भविष्य के बारे में आशंकाएं पैदा होना स्वाभाविक है। महासभा में 150-170 देशों के समर्थन से कोई प्रस्ताव पारित होता है, पर सुरक्षा परिषद में एक देश उसे निरस्त कर देता है। इस विडंबनापूर्ण स्थिति से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि वर्तमान और भविष्य को देखते हुए सुधार प्रक्रिया शुरू हो। यह काम जितना शीघ्र प्रारंभ होगा, उतना ही विश्व के लिए हितकारी होगा। इस दिशा में सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो दूसरे देश भी संयुक्त राष्ट्र की बात नहीं सुनेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। यह विश्व व्यवस्था के लिए बेहद नुकसानदेह होगा।

आज का इतिहास

1968 मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट 'मेनका' का सफल प्रक्षेपण हुआ।

1972 निकारागुआ की राजधानी मनागुआ में दो घंटे तक चले भूकंप ने जनजीवन तहस-नहस कर दिया और लगभग दस हजार लोग मारे गए।

1972 अमेरिकनफुटबॉल के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक, पिट्सबर्ग स्टीलर्स ने फ्रेंको हैरिस को पीछे छोड़ते हुए क्वार्टरबैक टेरी ब्रैडशॉ द्वारा एक प्लेऑफ गेम के पास एक पास का आईमैकेलेट रिसेप्शन बनाया।

1987 लिनेट स्कैकी फ्रॉमे, राष्ट्रपति गेराल्ड आर फोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए आजीवन कारावास की सजा काटकर एल्डरसन जेल से फरार हो गया।

1990 284 प्रदर्शन के बाद बैरीमोर थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में लेटिस एंड लवेज बंद हो गया।

1990 स्लोवेनिया में लगभग 88% आबादी ने यूगोस्लाविया के सोशलिस्ट फ़ेडरल रिपब्लिक से सेकेंडेड वोट दिया।

2008 विख्यात कथाकार गोविन्द मिश्र को उनके उपन्यास कोहरे के क़ैद रंग के लिए हिन्दी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 से नवाज़ा गया।

2010 फ्रांसीसी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए एक पुरुष अल्जीरियाई को नाइस में एक अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया; यह ऐसा पहला दंड था जिसे प्रशासित किया गया था।

2010 एक मानसूनी गर्त ने क्वींसलैंड में मूसलाधार बारिश ला दी, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, जिससे 38 लोग मारे गए और .2.38 बिलियन का नुकसान हुआ।

2011 ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, प्रिंस फिलिप एक अवरुद्ध कोरोनरी धमनी के इलाज के लिए अस्पताल में प्रवेश करते हैं।

2011 उत्तर कोरिया राज्य सभी दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडलों को स्वीकार करेंगे जो दिवंगत नेता किम जोंग-इल को उनके सम्मान का भुगतान करना चाहते हैं।

2012 चिली और अर्जेंटीना में, कोपाहे ज्वालामुखी के पास के क्षेत्रों में ज्वालामुखी गतिविधि के अलर्ट जारी किए जाते हैं, इसके बाद राख को उगलना शुरू कर दिया।

2012 उत्तर कोरिया द्वारा अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष उपग्रह का प्रक्षेपण दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय द्वारा विवादित है, जो दावा करता है कि यह 10,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल का प्रच्छन्न परीक्षण था।

चंदे के पैसे से कैसे चलेगी कांग्रेस ?

संजय तिवारी

कांग्रेस पार्टी के स्तर पर कितनी अस्तव्यस्त हो गयी है उसका उदाहरण इस बात से समझा जा सकता है कि डोनेट फॉर देश का कार्यक्रम तो उन्होंने लांच कर दिया लेकिन उसी नाम की वेबसाइट बनाना भूल गये। आज के इस सूचना क्रांति के युग में ऐसी गलती शायद ही कोई करे। लेकिन कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर भाजपा बैठी ही है कांग्रेस की गलतियों का लाभ उठाने के लिए। इसलिए डोनेट फॉर देश का कैम्पेन शुरु किया कांग्रेस ने और इसी नाम से डोमेन रजिस्टर करा लिया भाजपा ने।

अब दानदाताओं के सामने मुश्किल यह होगी कि अगर वो इंटरनेट पर डोनेट फॉर देश सर्च करेंगे तो भाजपा की बनाई वेबसाइट डोनेट फॉर देश.ऑर्ग दिख जाऐगी, जो भाजपा के लिए डोनेशन करने वाले पेज पर ले जायेगी। जबकि एक न्यूज पोर्टल ने इसी कैम्पेन से मिलता जुलता डोमेन बना भी लिया है और उसे अपने डोनेशन पेज पर रिडायरेक्ट भी कर दिया है। कांग्रेस में जिन भी लोगों ने यह कैम्पेन प्लान किया है उन्होंने यहां भी मानों कोई घोटाला कर दिया। देश के नाम पर पैसा मांगने का अभियान शुरु किया डोनेट फॉर देश के नाम से और उस डोनेशन के लिए जो वेबसाइट बनायी उसका नाम डोनेशनफॉरआईएनसी कर दिया। वैसे स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का अपना राजनीतिक चरित्र ऐसा बन गया है कि अगर उसके नेता कोई काम करें और उसमें घोटाला न हो तो भरोसा करना मुश्किल होता है कि क्या सचमुच यह कांग्रेस का ही नेता है। घोटाला और कांग्रेस एक दूसरे के लिए पर्यायवाची जैसे हो गये हैं। उसके नेता सत्ता में रहें या पार्टी का काम करें, घोटाला करने से नहीं चूकते। शायद इसीलिए इस डोनेशन कैम्पेन में डोमेन घोटाला हो गया।

कांग्रेस भाजपा की तरह कैडर आधारित पार्टी नहीं है। वह नेता आधारित पार्टी है इसलिए उसकी सफलता और असफलता उसकी लीडरशिप पर निर्भर करती है। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस में भाजपा के मुकाबले अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसका खामियाजा अक्सर कांग्रेस को एक पार्टी के रूप में उठाना पड़ता है। स्वतंत्रता के 75 सालों में लगभग 60 साल सत्ता में रहनेवाली कांग्रेस को अगर आज पार्टी चलाने के लिए चंदे की जरूरत महसूस हो रही है तो इसके पीछे उसके पास कैडर का न होना ही है। कांग्रेस एक सत्ता आधारित राजनीतिक दल है। उसके नेताओं का सारा जोर सदैव सत्ता पाने का रहता है जो कि

गलत भी नहीं है। राजनीतिक दलों का गठन और संचालन सत्ता प्राप्ति के लिए ही किया जाता है ताकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर %जनता की सेवा% कर सके। सत्ता आधारित दलों का संकट यह होता है कि उनके पास पार्टी कैडर नहीं होता। एक बार वह पार्टी अगर लंबे समय तक सत्ता से बाहर रह जाए तो उसके समर्थक ही नहीं, नेता भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। ठीक यही बीते दस सालों से कांग्रेस के साथ हो रहा है।

2014 में जब से कांग्रेस केन्द्र की सत्ता से बाहर गई, उसके नेता उसको छोड़कर जा रहे हैं। 2024 में अगर कांग्रेस ने मजबूत वापसी नहीं की तो नेताओं के जाने का सिलसिला और तेज भी हो सकता है। जो नेता सत्ता आधारित राजनीति को ध्यान में रखकर काम करते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं जिनकी सत्ता होती है। कांग्रेस के जो नेता भाजपा या दूसरे दलों में जा रहे हैं वो मान चुके हैं कि कांग्रेस निकट भविष्य में सत्ता में नहीं लौटनेवाली। जब पार्टी का ही कोई भविष्य नहीं तो फिर उनका क्या भविष्य होगा? राजस्थान और छत्तीसगढ की सत्ता से विदाई के बाद अब कांग्रेस के पास तेलंगाना और कर्नाटक की सत्ता बची है। झारखण्ड में वह गठबंधन की सरकार में है। स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस सत्ता में है ही नहीं तो कॉरपोरेट घराने भी उससे दूर हो रहे हैं। वो रिलायंस समूह भी अब कांग्रेस से दूर हो चुका है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे रिलायंस बनाने में कांग्रेस की सरकारों का ही योगदान रहा है। व्यावसायिक घरानों की भी मजबूरी होती है कि वो सत्ता के साथ रहें। उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना होता है कि विचारधारा के आधार पर किसी दल का समर्थन या विरोध करें। ऐसे में आज डोनेशन ड्राइव करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनायास नहीं कह रहे हैं कि अगर आप केवल अमीरों के पैसे से राजनीति करेंगे तो उनकी नीतियों को मानना पड़ेगा। वो जानते हैं कि कांग्रेस को अमीरों का पैसा तभी मिलेगा जब वो सत्ता में वापसी की संभावना दिखायेंगे। फिलहाल 2024 में भी ऐसा होता दिख नहीं रहा है तो जरूरी हो या मजबूरी उन्हें वोट और नोट के लिए जनता के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा। इसके लिए कांग्रेस महात्मा गांधी का उदाहरण भी दे रही है कि कैसे उन्होंने जनता के पैसे से स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। लेकिन कांग्रेसी नेता यह भूल रहे हैं कि अब न देश किसी का गुलाम है और न ही समाजवाद का स्वर्णयुग रहा जब निजी कारोबारी घरानों से संबंध को राजनीतिक भ्रष्टाचार समझा जाता था।

कांग्रेस ने ही नब्बे के दशक में जिस नव उदारवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की थी, उसने व्यापार और समाज को ही नहीं बदला, राजनीति को भी बदल दिया है। अब कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचानेवाली नीतियां बनाना आपके आर्थिक विकास के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। अब पिछले हफ्ते यूपी की योगी सरकार ने ऐसे कई कानून समाप्त कर दिये जिसके उल्लंघन पर व्यापारियों को जेल जाने का डर रहता था। ऐसी ही व्यवस्था को उदारवादी व्यवस्था कहा गया जिससे अब कोई राजनीतिक दल सरकार में आने के बाद पीछे नहीं हट सकता।

फिर चंदे की राजनीति के लिए कैडरबेस होना जरूरी होता है। कांग्रेस में समानांतर कैडर वाली जो व्यवस्था कांग्रेस सेवादल के रूप में थी अब वह कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा फहराने लायक भी नहीं बची है। फिर चंदा इकट्ठा कौन करेगा? कांग्रेस के नेता करेंगे भी तो उसमें भी घोटाला करेंगे क्योंकि 7 दशक में उन्होंने यही सीखा है। अगर कांग्रेस सचमुच चंदे की राजनीति करना चाहती है तो उसे पुनः सेवादल को सशक्त करना पड़ेगा और पूरी पार्टी को नेता आधारित बनाने की बजाय कैडर आधारित बनाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ऐसा करने की शुरुआत भी कर दे तो उसके लिए भविष्य के रास्ते खुल सकते हैं।

अभी का जैसा राजनीतिक माहौल है उसे देखकर नहीं लगता कि राष्ट्रवादी राजनीति का पारा बहुत जल्द उतरनेवाला है। उतरना शुरु भी हुआ तो उतरते उतरते पांच दस साल लग जाएंगे। इसका कारण यह है कि भाजपा कैडर आधारित पार्टी है और जैसे ही उसे लीडर मिलता है वह उछलकर सत्ता तक पहुंच जाती है। कांग्रेस यहीं पर कमजोर पड़ती है। अगर वह अपनी यह कैडर वाली कमजोरी दूर कर ले तो भले ही लंबे समय तक विपक्ष में रहना पड़े, कम से कम उसका राजनीतिक वजूद बचा रहेगा। अभी की जो कांग्रेस है वो चंदे के नाम पर अपने ही नेताओं से कुछ पैसा इकट्ठा भले कर ले, आम जनता पर उसकी अपील का कोई असर होगा, ऐसा लगता नहीं है।

चार राज्यों में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फंसा पेंच!

आशीष तिवारी

इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर महज 9 दिन बाकी हैं। इन 9 दिनों में सीट बंटवारे का पूरा फॉर्मूला गठबंधन के बड़े नेताओं के पास पहुंच जाएगा। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि तीन महत्वपूर्ण राज्यों में गठबंधन के घटक दलों की आपस में ही फ्रेंडली फाइट भी लोकसभा चुनाव में हो सकती है। पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में ऐसी फ्रेंडली फाइट की संभावना दिख रही है। हालांकि गठबंधन के नेताओं की ओर से इन राज्यों में आधिकारिक तौर पर घटक दलों के बीच की लड़ाई को लेकर कोई बयान तो नहीं आया है। सूत्रों की मानें तो इन राज्यों के नेताओं के बीच अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो बगैर किसी मनमुटाव के फ्रेंडली फाइट को लेकर भी सब कुछ तय हो चुका है। सोमवार को हुई गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर जब चर्चा हुई, तो उसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल समेत दिल्ली की भी बात हुई। सूत्रों की मानें तो यही वह चार राज्य हैं, जहां पर गठबंधन के बीच में तमाम आपसी तालमेल के दौरान फ्रेंडली फाइट की भी गुंजाइश नजर आ रही है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर शुरुआत से ही मतभेद चल रहे हैं। सूत्रों की मानें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए वह अपनी ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही है। जबकि कांग्रेस अपनी मौजूदा सीटों को लेकर मजबूत दावेदारी में है। सियासी जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को बड़ा फलक मिलने का अनुमान है। जबकि गठबंधन में सीटों के हिस्से में बड़े बंटवारे पर मामला फंस रहा है। यही वजह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फ्रेंडली फाइट की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में फ्रेंडली फाइट की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सूत्रों की मानें तो पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई है, लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। ऐसे में एक गुंजाइश यह भी बन रही है कि वहां पर गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रत्याशी मैदान में अपने-अपने दल के साथ उतरे और जीतने के बाद गठबंधन का हिस्सा बनें। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस तरह से फ्रेंडली फाइट को लेकर घटक दलों के बीच में आम राय नहीं बनी है। कहा यह भी गया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हर हाल में तय होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर गठबंधन के बैनर तले सीट शेयरिंग फॉर्मूले से ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा जाता है, तो उसका बड़ा सियासी फायदा होगा। इसी तरह दक्षिण के राज्य केरल में भी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फिलहाल शुरुआती दौर में बात बनती नजर नहीं आई है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हो सकता है। इसे गठबंधन फ्रेंडली फाइट का नाम देकर चुनावी समर में उतर सकता है। राजनीतिक विश्लेषण विष्णु शंकर कहते हैं कि फिलहाल तो शुरुआती दौर में इन तीन प्रमुख राज्यों के साथ दिल्ली में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर थोड़ा मामला फंसा हुआ दिख रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में गठबंधन के बीच में फ्रेंडली फाइट होने वाली है। राजनैतिक विश्लेषक राजीव चंद्रा कहते कि इसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हो सकता है। जबकि दिल्ली में भी यही स्थिति आ सकती है। इसी तरह से केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच स्थिति बन सकती है। जबकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में लड़ाई हो सकती है। हालांकि राजीव चंद्रा कहते हैं कि अगर इन चार राज्यों में सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है, जहां पर बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। इसके पीछे उनका तर्क है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन उनका कोई भी सांसद नहीं है।

सुरक्षा चूक, मिमिक्री और निलंबन के नाम रहा शीतकालीन सत्र

गुलाम अहमद

संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को ही खत्म हो गया। नए संसद भवन में आयोजित पहला और वर्तमान लोकसभा का अंतिम औपचारिक सत्र सुरक्षा चूक, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर उपजे विवाद और बड़ी संख्या में हुए विपक्षी सांसदों के निलंबन के नाम रहा। इस सत्र ने लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष के संबंधों में आई खटास और दूरी को और बढ़ा दिया। हालांकि इस दौरान देश के आपराधिक कानून में बदलाव लाने वाले तीन और दूरसंचार क्षेत्र में बदलाव लाने वाले अहम विधेयक समेत 18 विधेयक पारित किए गए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन से शुरू हुए सत्र का पहला हफ्ता शांति से बीता। हालांकि संसद पर आतंकी हमले के बरसी के दिन हुई सुरक्षा चूक से सियासी महाभारत शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए विस्तृत चर्चा के साथ गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। इस पर हुए विवाद के चलते दोनों सदनों से विपक्ष के रिकॉर्ड 146 सांसद निलंबित हुए। लोकसभा में कार्यवाही के अंतिम दिन तीन सांसदों के निलंबन के साथ ही दोनों सदनों में निलंबित सांसदों की संख्या 146 हो गई। इनमें लोकसभा के 112 और राज्यसभा के 34 सांसद शामिल हैं। चार बैठकों में कांग्रेस के 60, डीएमके के 21, जदयू के 14, टीएमसी के 21, सपा के चार, बसपा, आईयूएमएल, झामुमो, वीसीके, आरएसपी के एक-एक, एनसीपी के 4, सीपीएम के 5, सीपीआई के 3, एनसी के 2 सांसद निलंबित किए गए। शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में 65 घंटे तो लोकसभा में 61 घंटे 50 मिनट काम हुआ। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अफसोस जताते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से कार्यवाही बाधित करने के कारण लगभग 22 घंटे बर्बाद हुए। धनखड़ ने कहा, सदन की कुल उत्पादकता 79 प्रतिशत रही। 14 बैठकों के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्षी बेंचों के 2,300 से अधिक प्रश्नों को संबोधित किया गया। कुल 17 विधेयक पारित हुए। लोकसभा में 74 प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की गई। 14 बैठकें हुईं। सत्र में 18 विधेयक पारित किए गए। शीतकालीन सत्र में देश के आपराधिक कानून में आमूल-चूल बदलाव लाने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक पारित हुए। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र के ढांचे में बदलाव लाने वाले दूरसंचार विधेयक और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयक भी चर्चित रहे। डाकघर विधेयक, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन विधेयक भी पारित किए गए। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद चार विधेयकों के माध्यम से राज्य के राजनीतिक-प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव लाने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध नजर आई। राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ाई गई, बल्कि कश्मीरी पंडितों और पीओके का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। एक तिहाई संख्या महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक को कानूनी जामा पहनाया गया। कई वंचित जातियों को ओबीसी और एसटी वर्ग में शामिल किया गया। सुरक्षा में चूक और तकरार के कारण विपक्षी सांसदों के निलंबन से उपजे विवाद की आग में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी का सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले वीडियो ने घी डाल दिया। इस मामले में वीडियो बनाते देखे गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी निशाने पर आए। धनखड़ ने इसे जाट बिरादरी, सांविधानिक पद और किसान परिवार का अपमान बताते हुए राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

विश्वसनीयता में भी सबसे आगे हैं प्रधानमंत्री मोदी

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर विरोधियों द्वारा लाख आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते रहे हो पर इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में लोकप्रियता में दुनिया के दिग्गज नेताओं में शीर्ष पर कोई नेता है तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन या रुस के पुतिन हो या अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता के आसपास भी नहीं टिकते है। अमेरिका की कंसल्टेंसी फर्म मार्निंग कंसल्ट द्वारा इसी माह की शुरुआत में करवाये गए सर्वे में यह साफ हो गया है कि सर्वे में हिस्सा ले रहे दुनिया के देशों के लोगों में 76 फीसदी लोगों की पंहली पसंद नरेन्द्र मोदी रहे हैं। लोकप्रियता में नकारने वाले भी केवल 18 फीसदी ही है जबकि 6 फीसदी ने अपनी कोई राय उजागर नहीं की है। इससे पहले अमेरिकी थिंक टेंक प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 10 में से 8 व्यक्ति नरेन्द्र मोदी के प्रति सकारात्मक राय रखते हैं। यानी कि देश के 80 फीसदी लोग नरेन्द्र मोदी में विश्वास रखते हैं। 55 फीसदी लोगों की पहली पंसद नरेन्द मोदी है। देश की केवल 20 फीसदी आबादी नरेन्द्र मोदी को पसंद नहीं करती है।

लोकप्रियता की सूची में मजे की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इस लोकप्रियता की श्रेणी में 8 वें पायदान पर हैं। दरअसल विश्वव्यापी लोकप्रियता अर्जित करना कोई सामान्य बात नहीं होती है। हमारे देश के लिए तो यह और भी गर्व की बात हो जाती है कि हमारे नेता की लोकप्रियता दुनिया में पहले पायदान पर है। मजे की बरत यह है कि लोकप्रियता के साथ ही विश्वसनीयता में भी सबसे आगे हैं। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि लोकप्रियता में अव्वल आना इस मायने में बड़ी बात हो जाती है कि 76 फीसदी को मतलब साफ है कि यह लोकप्रियता का कोई मामूली

आंकड़ा नहीं है अपितु लोकप्रियता के दूसरे पायदान पर रहे मैक्सिकों के राष्ट्रपति एन्ड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर से पूरे दस प्रतिशत अधिक है। यानी कि नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का आंकड़ा 76 फीसदी है तो दूसरे पायदान पर रहे मैक्सिको के राष्ट्रपति की लोकप्रियता का आंकड़ा 66 फीसदी यानी कि दस फीसदी कम है। सूची के अनुसार तीसरे पायदान पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर ब्राजील, पांचवें पर आस्ट्रेलिया और छटे पायदान पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी रही है। मेलोनी जिसको लेकर पिछले दिनों सोशियल मीडिया पर एक से एक मीम्स चलाये जा रहे थे उनके और नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता में पूरे 35 फीसदी का अंतर है। देखा जाये तो नरेन्द्र मोदी का एग्रेसिव रवैया ही उनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण है। कठोर से कठोर और कड़े से कड़े निर्णय भी एक झटके में लेने की क्षमता और मोव को अपने पक्ष में करने क्षमता ही नरेन्द्र मोदी का लोकप्रियता के शिखर पर पंहुचाती है।

वैश्विक सम्मेलनों और मंचों पर ऐसा लगता है जैसे दुनिया के देशों का नेतृत्व नरेन्द्र मोदी ही कर रहे हो। बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी कि लगता यही है कि जैसे आज की तारीख में विश्व के नेताओं के कोई लीडर दिखाई देते है तो वह नरेन्द्र मोदी ही लगते हैं। भले ही इतर राय रखने वाले कुछ भी कहे या कुछ भी मनोभाव रखे पर अभी तो जो कुछ दिख रहा है वह साफ है और नरेन्द्र मोदी की सर्वमान्य नेता के रुप में भी प्रतिस्थापित करता है। अब मोदी विरोधी इसका कारण मोदी की एग्रेसिव मार्केटिंग, मीडिया मैनेजमेंट, तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ या कुछ भी कहे पर अंततोगत्वा जो दिख रहा है या जो सर्वे रिपोर्टस में आ रहा है या जैसा देशवासी अनुभव कर रहे हैं उसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता। अब इस यों भी समझा जा सकता है कि कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय और दुनिया के देशों द्वारा उफ् भी नहीं करना अगले की कूटनीतिक क्षमता को सिद्ध करता है।

पाकिस्तान और चीन को अलग थलग करना हो या फिर रुस यूक्रेन युद्ध या इजरायल हमास युद्ध कहीं भी नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। विरोधी देशों के संकट के दौरान सहायता में सबसे आगे रहना, अरब देषों को भी भारत के पक्ष में बनाये रखना, अमेरिका और रुस दोनों को ही साधे रहना अपने आप में बड़ी बात है। कोरोना दौर में भारतीय वैक्सीन के माध्यम से दुनिया के देशों के मानव इतिहास के सबसे बड़े संकटकाल में सहभागी के रुप में आगे आना लोकप्रियता और विश्वसनीयता बनाए रखने की बड़ी सफलता है। अमेरिका में ओबामा फिर ट्रम्प और अब जो बाइडन काल में भी समान अधिकार के साथ संबंध बनाए रखना बड़ी बात है। पाकिस्तान को दुनिया के देशों से अलग थलग करना तो मोदी के लिए मामूली बात सिद्ध हुई है। दरअसल आज के दौर में वैश्विक नेता के लिए बोल्ड होने, एग्रेसिव होने, कठोर व त्वरित निर्णय लेने वाले नेता लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। अच्छे बुरे परिणाम की चिंता कर निर्णय की उहापोह में फंसे नेता आज के लोगों की पसंद हो ही नहीं सकते। इसका बड़ा कारण दुनिया में वैश्विक संकटों का दौर चलना है। संकटों के दौर में लोगों का यह मानना रहता है कि हमें आलोचना प्रत्यालोचना या आगा पीछा सोच कर निर्णय लेने वाला नहीं अपितु त्वरित और कठोर निर्णय लेने वाला नेता चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेन्द्र मोदी इस पर खरे उतरे हैं।

सत्ता पक्ष की चौधराहट या विपक्ष की बौखलाहट ?

संजय तिवारी

हम भारतीयों का स्वभाव है कि हम सिर्फ संकट में एक होते हैं। जैसे ही संकट बीतता है हम आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। कम से कम इस बार संसद सत्र में यही नजारा दिखाई दे रहा है। अभी 13 दिसंबर को सभी सांसद संसद भवन पर हमले में बलिदान होनेवाले रक्षकों को श्रद्धांजलि देकर आये ही थे कि एक बार फिर लोकसभा में हमलावर घुस गये। लोकसभा में जैसे ही बाहरी हमलावर घुसे तो पलक झपकते सभी सांसद एक हो गये। कुछ सांसदों ने मिलकर हमलावरों की पिटाई तक कर दी।

उस समय न कोई भाजपाई था न कांग्रेसी। न तृणमूल वाला और न ही कोई और। पलक झपकते सब आपसी दुश्मनी भुलाकर उन हमलावरों के खिलाफ एकजुट हो गये। लेकिन जैसे ही संकट टला, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने उसी हमले को ही अपने लिए लड़ने का मुद्दा बना लिया। अब विपक्ष कह रहा है कि गृहमंत्री उस पूरे मामले में बयान दें और जब तक ऐसा नहीं होगा वो संसद नहीं चलने देंगे। इस बहिर्गमन के बीच ही संसद भवन के दरवाजे पर कुछ सांसद धरने पर बैठ गये। यहां तक कि तृणमूल के सांसद कल्याण बनर्जी उसी धरने में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल तक उतारने लगे।

यहां से विवाद का दूसरा अध्याय खुल गया। स्वयं जगदीप धनखड़ ने इस पर दुख जताते हुए कह दिया कि यह उनका नहीं बल्कि सभापति के आसन, किसान समाज और उनकी जाति का मजाक उड़ाया गया है।

उनके इस बयान ने आग में घी का काम किया। यह सीधे सीधे राजनीतिक बयान था जिस पर प्रतिक्रिया आनी ही थी। अब विपक्षी सांसदों को नया मुद्दा मिल गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कह दिया कि कई बार मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो क्या अब मैं ये कहूं कि मेरे दलित होने के कारण मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता?

इस पूरे मामले में जगदीप धनखड़ कल्याण बनर्जी की मिमिक्री से अधिक राहुल गांधी की वहां मौजूदगी से दुखी थे। कांग्रेस के नेताओं को इशारों इशारों में उन्होंने यह बात बताई भी लेकिन खुद राहुल गांधी से जब मीडिया द्वारा इस पर सफाई मांगी गयी तो उन्होंने इस मामले पर कुछ न बोलते हुए वही पुराना अडाणी राग अलाप दिया। उनके मुताबिक संसद में विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मोदी सरकार अपनी मनमानी कर रही है।

इस बीच ऐतिहासिक रूप से 143 सांसदों को सदन की कार्रवाही से बर्खास्त किया जा चुका है। इनमें 97 लोकसभा के और 46 राज्यसभा के सांसद हैं। इनकी बर्खास्तगी के आदेश में कहा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान संसद भवन की सीढियों पर चढ़ने तक की अनुमति नहीं होगी। इन बर्खास्त सांसदों का दैनिक भत्ता भी रोक दिया गया है। जाहिर है दोनों सदनों के प्रमुखों की ओर से की गयी ये बड़ी सख्त कार्रवाई है जो विपक्ष को यह कहने का मौका देगी कि सत्ता पक्ष अपनी तानाशाही कर रहा है। कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम ने कहा भी है कि अब यही चलन बनने जा रहा है। जो मेरा रास्ता है वही सही है। अगर आप उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आपको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा।

इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है और केन्द्र सरकार जरूरी विधेयकों को एकतरफा पारित भी करती जा रही है। लेकिन आम आदमी के लिए सवाल तो यह है कि इस संसदीय गतिरोध के लिए दोषी कौन है? अगर आम आदमी पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से संसदीय मर्यादा और विशिष्ट आचरण की उम्मीद करता है तो इसके दिन लद गये। अब संसद भवन शिष्टता, शालीनता और चुटीले अंदाज में अपनी बात कह देने की जगह नहीं रही। उसकी जगह लाइव प्रसारण वाली संसद एक ऐसा अखाड़ा बन गयी है जहां दोनों ही पक्ष के लोग अपने अपने वोटरों को साधने की कोशिश करते हैं।

अगर आज सत्ता पक्ष को कल्याण बनर्जी की मिमिक्री बुरी लग रही है तो विपक्ष को लगता है सत्ताधारी पार्टी का नेता तो खुद ऐसा करता है फिर किस मुंह से बीजेपी ऐसे आरोप लगाती है? मतलब गिरावट और पतन में दोनों पक्ष एक दूसरे की बराबरी करने में ज्यादा सहज हैं। दोनों ही पक्षों का अपना अपना एजंडा है और कोई भी इससे पीछे हटना नहीं चाहता। जो दल सरकार में होता है उसका प्रयास होता है कि अधिक से अधिक संसदीय कार्यवाही हो और उसके विधेयक पारित हो जाएं। वहीं विपक्ष का अब ऐसा स्वभाव बनता जा रहा है कि जैसे भी हो सदन ही न चलने दिया जाए।

इस तरह यह संसदीय गतिरोध न पहला है और न आखिरी। संसद न चलने देने का रिकार्ड बनाना हो तो भाजपा हो या कांग्रेस, विपक्ष में रहते हुए कोई पीछे नहीं रहता। लेकिन जो नया चलन देखने को मिल रहा है वह यह कि अब संसद के बाहर के मुद्दों पर संसद गतिरोध तो होता ही है, संसदीय गतिविधि को लेकर भी बार बार गतिरोध पैदा हो रहा है। संसद के भीतर की समस्याओं को लेकर सांसद सदन के बाहर धरना दे रहे हैं और मार्च कर रहे हैं। इसलिए ऐसे हालात में न तो किसी एक पक्ष को दोषी करार दिया जा सकता है और न ही दूसरे पक्ष को निर्दोष। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं जिससे अगर किसी को नुकसान है तो उस संसदीय गरिमा का जो लोकतंत्र में राजनीतिक समुदाय के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। बार बार संसद में होनेवाले इस तरह के हंगामे, गतिरोध के कारण आम आदमी की संसदीय कार्रवाही में लाइव प्रसारण के बाद भी कोई रुचि नहीं रहती। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर जनता ही उनकी गतिविधियों से विमुख हो गयी तो फिर यह सारा हंगामा और प्रदर्शन कर किसके लिए रहे हैं?

भारत के संसदीय लोकतंत्र का इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सत्ता में जो भी दल बैठ जाए या विपक्ष में जो भी बैठ जाए, उसका व्यवहार नहीं बदलता। कल तक कांग्रेस सत्ता पक्ष थी तो बीजेपी से उम्मीद करती थी कि वह सदन को चलने में मदद करे। आज बीजेपी सत्ता में है तो यही उम्मीद वह कांग्रेस या अन्य विपक्षी सांसदों से कर रही है। जो दल सत्ता में होता है वह चौधरी हो ही जाता है और जो विपक्ष में रहता है उसके विरोध को बौखलाहट बता ही दिया जाता है। कुछ सालों से इसमें तो कोई बदलाव आया नहीं है। भविष्य में आ जाए तो इसे भारत के संसदीय लोकतंत्र का पुनर्जीवन ही कहा जाएगा।

क्रिसमस पार्टी के लिए हो रहीं रेडी तो जींस के साथ इन कपड़ों को करें पेयर

क्रिसमस नजदीक आते ही पार्टियों का दौर चलने लगता है। दोस्तों के साथ क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर की पार्टी का मजा लेने के लिए लड़कियां बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से रेडी होना चाहती हैं। लेकिन कड़ाके की सर्दी स्टाइल पर पानी फेर देती है। सर्दी में ड्रेस और शार्ट्स पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर जींस या पैंट का ही ऑप्शन रह जाता है। लेकिन अब जींस और पैंट में भी आप स्टाइलिश दिख सकती हैं। बस पैंट या जींस के साथ इस तरह के कपड़ों को पेयर करें।

शिमरी स्वेटर

आजकल मार्केट में कई वैराइटी के स्वेटर मिल जाते हैं। आप चाहें तो आसानी से शिमर वर्क वाले स्वेटर खरीद सकती हैं। हाई नेक, राउंड नेक, वी नेकलाइन और रैप डिजाइन के काफी सारे स्वेटर आसानी से मिल जाएंगे। जिसे आप जींस या पैंट के साथ पेयर किया जा सकता है।

कलरफुल ब्लेजर

कलरफुल या ब्लिंगी इफेक्ट वाले ब्लेजर भी पार्टी रेडी लुक दे सकते हैं। इसे आप किसी भी स्टाइलिश टॉप के साथ पेयर करें। ताकि जरूरत पड़ने पर इसे हटा भी सकें और गॉर्जियस लुक में नजर आएं।

वेलवेट फैब्रिक

ठंड से बचना है तो वेलवेट फैब्रिक के टॉप को भी ट्राई कर सकती हैं। या फिर वेलवेट पैंट या जंपसूट भी काफी स्टाइलिश लुक देंगे। इन्हें आप स्ट्रैपी हील्स के साथ पेयर करें।

ओवरसाइज स्टाइलिश स्वेटर

लेदर पैंट्स को ओवरसाइज स्वेटर के साथ पेयर करें। राउंड शेप नेकलाइन को कंधे से सरकाकर ऑफ शोल्डर लुक दिया जा सकता है। साथ ही ठंड से बचाने में भी ये स्वेटर मदद करेंगे। तो जरूरी नहीं कि ग्लैमरस दिखने के लिए शार्ट ड्रेसेज पहनी जाएं। आप स्वेटर और जींस के साथ भी स्टाइलिश नजर आ सकती हैं। बस इन स्टाइलिंग आइडियाज को ट्राई करें।

सर्दियों में स्किन ड्राई और काली नजर आने लगी है तो सोने से पहले लगाएं ये चीजें

सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। ड्राईनेस के साथ ही बहुत सारे लोगों को स्किन पर कालापन और पपड़ी सी नजर आती है। जिसे दूर करने के लिए दिनभर लगा मॉइश्चराइजर भी असर नहीं दिखा पाता है। ऐसे में जरूरी है कि कुछ खास बातों का ध्यान रखने के साथ ही रात के वक्त स्किन केयर रूटीन को जरूर फॉलो करें। जिससे कि स्किन को रातभर बिना पानी के आसानी से मॉइश्चराइजेशन मिल सके। तो चलिए जानें ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के लिए किन चीजों को लगाएं।

ग्लिसरीन और गुलाबज

गुलाबजल को नेचुरल टोनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसी शीशी में ग्लिसरीन की आधी से ज्यादा मात्रा भरें और बाकी शीशी गुलाब जल से भर लें। अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स करें और रख लें। रोजाना रात को सोने से पहले इस मिक्सचर को चेहरे, हाथों-पैरों पर लगाएं। ये स्किन को सॉफ्ट करने में मदद करेगी।

बादाम का तेल

रात को सोने से पहले हाथों में कुछ बूंदे बादाम के तेल की लेकर हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें। ये ना केवल चेहरे को मॉइश्चराइज करने का काम करता है बल्कि स्किन को यंग भी बनाता है।

गर्म पानी से रहें दूर

चेहरे को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वहीं नहाने के लिए भी बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। इससे स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म होने लगता है और स्किन पर ज्यादा पपड़ी और ड्राईनेस नजर आने लगती है।

डेड स्किन जरूर निकालें

रोजाना नहाने से पहले स्किन पर जमा ड्राई डेड स्किन को जरूर हटाएं। इस डेड स्किन को हटाने के लिए आटे के चोकर में दही मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को हल्के हाथों से लेकर चेहरे, गर्दन, हाथों, पैरों को मसाज करें और पानी से धो लें। ये स्किन के डेड स्किन को हटाने के साथ ही नेचुरली मॉइश्चराइज करने में मदद करेगा।

ना करें साबुन का इस्तेमाल

सर्दियों में साबुन का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। ये स्किन को ड्राई और डल बना देंगी। आप नेचुरल स्क्रब और बॉडी वॉश की मदद से स्किन को साफ करें।

चेहरे को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वहीं नहाने के लिए भी बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें।

झड़ते बालों से परेशान हैं तो इन दो चीजों को मिलाकर लगाएं

टूटते-झड़ते बाल काफी बेकार लगते हैं। खासतौर पर महिलाएं अपने कमजोर बालों से सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं। घने, लंबे और मजबूत बाल तो हर किसी की चाहत होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि सबको ऐसे बाल आसानी से मिल जाएं। लेकिन बालों को मजबूत बनाने के लिए कुछ छोटे उपायों को अपनाकर झड़ना रोका जा सकता है। साथ ही बालों की नई ग्रोथ भी होने लगेगी। तो चलिए जानें ऐसा ही कारगर नुस्खा जो बालों को झड़ने से रोकने के साथ ही घना बनाने में मदद करेगा।

कैस्टर ऑयल से दूर होगा हेयर फॉल

बालों का झड़ना तेजी से रोकना चाहते हैं तो कैस्टर ऑयल बेस्ट ऑप्शन है। इसकी मदद से बालों को टूटने से रोककर मजबूत बनाया जा सकता है। कैस्टर ऑयल को ही अरंडी का तेल भी कहते हैं। ये तेल काफी ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। साथ ही इसमे पोषक तत्व की मात्रा भी ज्यादा होती है। जिसकी मदद से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और बालों का झड़ना बंद होता है। कैस्टर ऑयल में रिकिनोलेइक एसिड होता है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। जिससे बालों में ग्रोथ तेज होती है।

कैस्टर ऑयल को कैसे लगाएं बालों में

बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं तो कैस्टर ऑयल को इस चीज के साथ मिलाकर लगाएं।

कैस्टर ऑयल लें।

इसमे 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर मिक्स कर लें। करीब दस से पंद्रह मिनट इस पेस्ट को छोड़ दें। फिर बालों की जड़ों में ये पेस्ट लगाकर करीब 30-40 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। सप्ताह में दो बार इस पेस्ट को बालों में लगाने से कुछ ही इस्तेमाल के बाद बालों का झड़ना कम हो जाएगा।

सेहत ही नहीं त्वचा के लिए भी फायदेमंद हैं ये फल और सब्जियां

कई ऐसे फल और सब्जियां होती हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में सहायक होती हैं। आज हम आपको इन फलों और सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनके सेवन से आपको सेहत संबंधी लाभ मिलने के साथ ही स्किन संबंधी फायदे भी मिलते हैं।

फलों और सब्जियों का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी होता है। फलों और सब्जियों में मौजूद फाइबर न सिर्फ पाचन को स्वस्थ रखता है, बल्कि इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इसके अलावा यह हमारी त्वचा के लिए भी लाभकारी होती है।

कई ऐसे फल और सब्जियां होती हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में सहायक होती हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इन फलों और सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनके सेवन से आपको सेहत संबंधी लाभ मिलने के साथ ही स्किन संबंधी फायदे भी मिलते हैं।

शकरकंद

आपको बता दें कि सेहत के साथ-साथ शकरकंद स्किन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। शकरकंद में बीटा केरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो हमारी त्वचा को नेचुलर रूप से हेल्दी रखने में मददगार होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी पायी जाती है। जो त्वचां संबंधी इंफेक्शन के खतरे को कम करता है। शकरकंद को उबालकर खाने से त्वचा को फायदा मिलता है।

एवोकाडो

स्किन के लिए एवोकाडो का सेवन भी लाभकारी माना जाता है। एवोकाडो में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके सेवन से आपकी त्वचा अंदर से साफ होता है। जब स्किन अंदर से साफ होती है तो बाहर भी इसका निखार साफ पता चलता है। आप चाट या फिर शेक के तौर पर भी एवोकाडो का सेवन कर सकते हैं।

खीरा

खीरा में पानी की पर्याप्त मात्रा पायी जाती है। इसके सेवन से त्वचा हाइड्रेड रहती हैं। वहीं खीरे में एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। खीरे के नियमित सेवन से स्किन हाइड्रेट रहने के साथ ही मॉइस्चराइज रहती है।

संतरा

विटामिन सी से भरपूर संतरा त्वचा की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। संतरा में आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो स्किन को नेचुरल तरीके से हेल्दी और ग्लोइंग रखता है। साथ ही संतरे के सेवन झुर्रियां कम होने के साथ कोलेजन बढ़ता है।

पपीता

हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में पपीता भी अहम भूमिका निभाता है। पपीता में मिनरल्स के साथ-साथ विटामिन-ए, विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है। जो स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। साथ ही यह त्वचा को हाइड्रेट भी रखता है। ऐसे में आप रोजाना पपीते का सेवन कर सकते हैं।

राशिफल

मेष
आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस से रिलेटेड आप अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग करेंगे व्यापारिक लाभ पर चर्चा करेंगे।

वृष
आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। ट्रांसपोर्ट के व्यापारी आज किसी बुकिंग से अच्छा लाभ कमाएंगे।

मिथुन
आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। नयी कार्य योजनाओं को स्टार्ट करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा ।

कर्क
आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। दूर-दराज़ के लोगों से सम्पर्क बनाकर बिजनेस करना लाभकारी रहेगा और बिजनेस भी दूर तक फैलेगा।

सिंह
आज आपका दिन नयी-नयी खुशियाँ लेकर आएगा। अच्छे भविष्य के लिए आप कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।

कन्या
आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे और सफल भी रहेंगे।

तुला
आज आपका दिन शानदार रहेगा। अधिक भागदौड़ वाला काम होने के बावजूद भी आप पॉजिटिव रहेंगे। आपके अच्छे व्यवहार के जरिये आपके कुछ नए दोस्त बन सकते है।

वृश्चिक
आज आपका दिन आपके लकी रहने वाला है। इस राशि के जो लोग सिंगिंग में अपना करिअर बनाना चाहते है उनके लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला है।

धनु
आज आपका दिन बेहद खुशहाल रहेगा। आज आप फिजूल में अपना समय ना बिताएं। कार्यों को पूरा करने पर ध्यान लगायें।

मकर
आज आपका दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। कामकाज के मामले में आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही सुलझ जायेगी।

कुंभ
आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। पेरेंट्स बच्चों के साथ किसी शोपिंग मॉल में घूमने जायेंगे। छात्रों को नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको सब साथ मिलकर पूरा करेंगे।

मीन
आज आपका दिन ताजगी से भरा रहेगा। इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा।

शादी के फंक्शन में मिनिमल लुक में भी दिखेंगी स्टाइलिश

शादी में खासतौर पर लड़कियां लहंगा पहनती हैं। वहीं लहंगे में कई डिजाइन और पैटर्न मिल जाते हैं। आज हम आपको सिल्क लहंगे कि कुछ डिजाइंस के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही इस लहंगे को स्टाइल करने के कुछ आसान टिप्स के बारे में भी जानेंगे।

आज के समय में हर कोई स्टाइलिश दिखने की चाहत रखता है। वहीं इन दिनों वेडिंग सीजन की शुरूआत हो चुकी है। शादियों की तैयारियां वैसे तो महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। शादी में खासतौर पर लड़कियां लहंगा पहनती हैं। वहीं लहंगे में कई डिजाइन और पैटर्न मिल जाते हैं। बता दें कि फैशन का ट्रेंड काफी तेजी से बदल रहा है। आजकल सिल्क लहंगा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सिल्क के लहंगे में कई डिजाइन और पैटर्न देखने को मिल जाते हैं।

ऐसे में अगर आप भी किसी शादी में लहंगा पहनने की सोच रही हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको सिल्क लहंगे कि कुछ डिजाइंस के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही इस लहंगे को स्टाइल करने के कुछ आसान टिप्स के बारे में भी जानेंगे। जिससे कि शादी जैसे फंक्शन में आपको स्टाइलिश और मिनिमल लुक मिल सके।

बनारसी सिल्क लहंगा

आजकल बनारसी सिल्क साड़ी के साथ-साथ सिल्क लंहगा भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसमें आपको कई पैटर्न मिल जाएंगे। बता दें कि इस तरह के बनारसी सिल्क लहंगे आपको मार्केट में 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में मिल जाएंगे।

वहीं आप इस बनारसी सिल्क लहंगे के साथ गले में चोकर के साथ मैचिंग स्टड्स इयररिंग्स को कैरी कर सकती हैं। जो आपके लुक में चार चांद लगाने का काम करेगा।

गोटा-पट्टी डिजाइन सिल्क लहंगा

इसके अलावा आजकल गोटा-पट्टी डिजाइन वाला सिल्क लहंगा काफी चलन में हैं। इस तरह का लहंगा आपको मार्केट में 2500 से 4000 रुपए तक के बीच में मिल जाएगा। बता दें कि इस तरह के लहंगे के साथ आप पर मेसी लुक वाला हेयर बन खूब जचेगा।

पेस्टल कलर सिल्क लहंगा

अगर आप शादी में दिन के फंक्शन में लाइट कलर का आउटफिट पहनना चाहती हैं। तो पेस्टल कलर सिल्क लहंगा पहनना चाहिए। वहीं दिन के फंक्शन के लिए इस तरह का सटल कलर एकदम परफेक्ट है। यह आपको सॉफ्ट लुक देने में मदद करेगा। इसके साथ आप लो मेसी लुक वाली पोनीटेल कर सकती हैं।

हरी सब्जियां काटकर काले हो रहे हैं हाथ? साफ करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

किचन में काम करने वाली महिलाओं की अक्सर ये शिकायत रहती है कि सब्जियों को काटकर उनके हाथ खराब दिखने लगते हैं। खासकर ऐसा सर्दियों में होता है। क्योंकि सर्दी में हरी सब्जियां आना शुरू हो जाती हैं, ऐसे में उन सब्जियों को काटने पर हाथ काल हो जाते हैं। अगर इस तरह के हाथों को साफ ना किया जाए तो ये बहुत गंदे दिखने लगते हैं। ऐसे में हरी सब्जी काटने के बाद आप अपने हाथों को साफ करना चाहते हैं तो कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। ये तरीके महिलाएं आसानी से फॉलो कर सकती हैं। जानिए, हाथों की सफाई के बेहतरीन तरीके-

सब्जी काटने के बाद कैसे साफ करें हाथ-

1) सब्जी काटने के बाद हाथ काले हो गए हैं, तो साफ करने के लिए इन्हें गरम पानी में भिगोएं। इस पानी में आप नींबू या फिर शैम्पू मिला सकती हैं। इससे उंगलियां भी अच्छे से साफ होंगी और नाखुन भी।

2) हाथों को साफ करने के लिए आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए टमाटर के एक छोटे टुकड़े को लें और फिर इसे हाथों पर अच्छी तरह से रगड़ें। चाहें तो टमाटर की जगह नींबू भी रगड़ सकती हैं।

3) अगर हाथ बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं और बहुत नुस्खे अपनाने के बाद भी साफ नहीं हो रहे हैं तो आप हथेलियों पर थोड़ा सिरका लगाकर रगड़ें और बाद में साबुन और पानी से हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें।

4) हाथों को साफ करने के लिए आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए या तो हाथों को दूध में डुबोकर रख लें या फिर थोड़ा सा दूध लगाकर रगड़ें।

5) हाथ साफ करने के लिए कच्चा आलू भी काम आ सकता है। इसके लिए आलू की स्लाइस को हाथों में रगड़ सकते हैं। या फिर कच्चे आलू को कद्दूकस करके यूज कर सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट हो सकते हैं इमैनुएल मैक्रों

नईदिल्ली। भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को 2024 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। समाचार एजेंसी ने विकास से परिचित लोगों का हवाला देते हुए शुक्रवार को बताया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी में नई दिल्ली आने में असमर्थता जताई। ऊपर उद्धृत लोगों ने कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह विकास तब हुआ जब पीएम मोदी ने जुलाई में फ्रांस का दौरा किया और पेरिस में बैस्टिल डे (फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस) समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। बैस्टिल दिवस 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है।

पंजाब कांग्रेस का ऐलान, आप के साथ गठबंधन नहीं करेंगे

चंडीगढ़। लुधियाना के जगराओं की दाना मंडी में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए आप सरकार के खिलाफ विरोध रैली के दौरान पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने घोषणा की कि अगले लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक के तहत आप के साथ कोई भी गठबंधन उन्हें अस्वीकार्य है। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी वाली रैली में यह घोषणा करने वाले नेताओं में विधायक परगट सिंह, पीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा शामिल थे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि उन्हें पंजाब में आप के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह लड़ाई लड़ेंगे। वारिंग ने यह भी कहा कि वह पंजाब कांग्रेस नेतृत्व और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। पीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू साझा मंच से गायब थे।

हमने नहीं, विपक्षी नेताओं ने खुद निलंबन का अनुरोध किया

नई दिल्ली। सांसद के शीतकालीन सत्र में बाधा डालने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष को फटकार लगाई है। उन्होंने विपक्ष को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार सांसदों को निलंबित करने के लिए इच्छुक नहीं थी, लेकिन विपक्षी पार्टी के कुछ सदस्य अपने ही सहयोगियों के निलंबन का अनुरोध लेकर आए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अगर विपक्षी को तीन नए आपराधिक कानूनों में कुछ गलत लगता है तो वह इसके खिलाफ अदालत में जा सकती है। सांसदों के निलंबन पर उन्होंने कहा, हमने उन्हें निलंबित नहीं किया था, हम उनसे अनुरोध कर रहे थे। लेकिन जब हमने कुछ सांसदों को निलंबित किया तो उनके कई सहयोगी हमारे पास निलंबन की मांग लेकर आए। कांग्रेस इस स्तर तक गिर गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के फ्लोर मैनेजर सदन में प्लेकार्ड लाने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी।

संसद की बहस में जाति को बीच में लाना निराशाजनक

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल किए जाने के मामले में सियासत गरमा गई है। सभापति के अपमान के विरोध में भाजपा लगातार विपक्षियों पर निशाना साध रही है। हालांकि, इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इस बात पर अफसोस जताया कि संसद में महत्वपूर्ण विषय पर हो रही बहस में जाति को बीच में लाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि संसद में गंभीर बहस के दौरान जाति का उल्लेख किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से 21वीं सदी में छोटी सोच से आगे बढ़ने का आग्रह किया। इस बयान पर चिदंबरम ने कहा कि यह निराशाजनक है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर हो रही बहस में जाति को बीच में लाया जाता है। यह भी निराशाजनक है कि किसी व्यक्ति के जन्म स्थान का इस्तेमाल व्यक्ति की आलोचना करने के लिए एक तर्क के रूप में किया जाता है।

मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली में डटे सीएम मोहन यादव

भोपाल। मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री इन दिनों मंत्रिमंडल गठन को लेकर भोपाल से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। इस बीच सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को प्रदेश के सांसदों के साथ डिनर किया। गुरुवार को डिनर के बाद मध्यप्रदेश के सीएम यादव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शुक्रवार सुबह डॉ. यादव प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम यादव के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। इसी बीच सीएम की हाईकमान के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसी संभावना है कि 23 या 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों यानी मंत्री रह चुके नेताओं के बजाय नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है।

इंडिया गठबंधन ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया

आप हमें जितना कुचलेंगे, हम उतना ही ऊपर बढ़ेंगेः खड़गे

नईदिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के एक दिन बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता संसद से 146 सांसदों के सामूहिक निलंबन के विरोध में देश भर में सड़कों पर उतर आए हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान रिकॉर्ड संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जवाब मांगना शुरू कर दिया था, जिसने देश को सदमे में डाल दिया था। 14 से 22 दिसंबर तक, लोकसभा और राज्यसभा से एक साथ कुल 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था । सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने अव्यवस्थित आचरण और सदन की कार्यवाही में बाधा डाली। अब इंडिया ब्लॉक के नेता दिल्ली के जंतर-मंतर पर निलंबन के विरोध में एकजुट हुए हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर लोकतंत्र बचाओ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी शामिल हैं।

जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच खरगे ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते कहा, जितना आप हमें कुचलना चाहेंगे, हम उतना ऊपर बढ़ेंगे। हम देश को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, संविधान के उच्च पद पर बैठने वाले लोग कहते हैं कि मेरी जाति के कारण मेरा अपमान किया जा रहा है। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी?

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा, हमारे संविधान के तहत सभी को बोलने का अधिकार है। जब हम सांसद में नोटिस देते हैं तब हमें नोटिस पढ़ने का भी मौका नहीं दिया जाता है। तब मैंने बोला कि भाजपा एक दलित नेता को बोलने नहीं देती है? आप हमसे हमारे बोलने के अधिकार को छीन नहीं सकते। यह आजादी हमें जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी से मिली है। आप विपक्षी सांसदों को निलंबित कर देते हैं और निर्विरोध कानून पारित करते हैं। हमें मिलकर लड़ना होगा।

मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में हुए आतंकी हमले पर शोक जताते हुए कहा कि भारत आतंकबाद के संकट के खिलाफ एकजुट है। इस हादसे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हम

राजौरी और पीर पंजाल में हो रहे जघन्य हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। सेना के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस दुख के मौके पर हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं जवानों के परिजनों के साथ है। हम घायल हुए जवानों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि नेता देश की 140 करोड़ जनता के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा हम संसद और संसदीय गरिमा के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे...भारत में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अगर संसद को विपक्ष के बिना चलाना है, अगर सवाल पूछने की आजादी नहीं है, अगर सरकार की जवाबदेही नहीं है तय है, और अगर संविधान का पालन नहीं किया जाएगा तो संसद का क्या मतलब रह जाएगा। हम ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ रहे हैं, न डरेंगे, न थकेंगे, न रुकेंगे।

कांग्रेस नेता मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा कि सांसदों का सामूहिक निलंबन दिखाता है कि यह लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 या 6 ठीक हैं लेकिन लगभग 150 सदस्यों को निलंबित करना लोकतंत्र नहीं है। यह संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर सभी सांसद बाहर होंगे तो संसद कैसे चलेगी?...ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। एक सांसद के पास विशेषाधिकार है अपनी बात आगे रखने के लिए..। कांग्रेस के अरविंदर लवली ने निलंबन को लोकतंत्र के लिए धब्बा बताया। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर भारतीय को इस पर गर्व है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में राज्यसभा और लोकसभा में जो हुआ वह भारत के लोकतंत्र पर एक धब्बा है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने भी केरल के तिरुवनंतपुरम में राजभवन के पास संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ धरने का आयोजन किया है। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सभी राष्ट्रवादी संगठनों से देश में लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया और कहा कि एक साथ आने और एक स्वर में संदेश भेजने की जरूरत है। निलंबन पर बोलते हुए, कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि संसद सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और 700 से अधिक सांसद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सांसद ने कहा, ...सरकार को सांसदों को निलंबित करने और सदन चलाने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही और अलोकतांत्रिक है...। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन स्थल पर बोलते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं... सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी ने कहा, हमें उन लोगों से लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है जो वर्तमान में सत्ता में हैं। संसद में सुरक्षा उल्लंघन की घटना के लिए भाजपा को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि विपक्ष की ओर से गृह मंत्री से बयान की मांग करना स्वाभाविक है, और कहा कि सरकार उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं देने पर अड़ी हुई है। तो संसद के भीतर विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार की प्रतिक्रिया विपक्ष के 146 सदस्यों को निलंबित करना और कानून लागू करना था, जिसके भारत में लोगों के दैनिक जीवन पर दूरगामी परिणाम होंगे... सरकार चाहती है कि संसद जो बिना किसी चर्चा के केवल अपने सभी कानूनों पर मोहर लगाने का सदन बनकर रह जाएगी...उन्होंने कहा।

खरगे के नाम पर रूठे बिहार के मुख्यमंत्री को मनाने की कोशिश

राहुल गांधी ने खुद नीतीश कुमार को किया फोन

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक मीटिंग में पीएम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर कथित नाराजगी के बाद शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। जनता दल (यूनाइटेड) के सूत्रों के मुताबिक, राहुल ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किए जाने पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया। बनर्जी और केजरीवाल ने कहा था कि खड़गे देश के पहले दलित प्रधान मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। एमडीएमके नेता वाइको सहित कई नेताओं ने विपक्षी समूह की बैठक के बाद इसकी पुष्टि की और कहा कि खड़गे ने नेताओं से कहा कि पहले जीतना और गठबंधन की ताकत बढ़ाना महत्वपूर्ण है जबकि बाकी सब कुछ बाद में तय किया जा सकता है। राहुल और नीतीश ने फोन पर बातचीत के दौरान गठबंधन की मजबूती पर भी चर्चा की। बिहार कैबिनेट विस्तार पर अपनी बातचीत के दौरान, जहां राहुल ने नीतीश की भूमिका पर जोर दिया, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने गांधी से कहा कि वह खड़गे के संबंध में प्रस्ताव से अनजान थे। सूत्रों के मुताबिक, नीतीश ने राहुल गांधी को यह भी आश्वासन दिया कि वह किसी भी समय कैबिनेट में कांग्रेस मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर नीतीश ने इसके लिए लालू यादव की ओर से स्पष्टता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उसके उम्मीदवारों का फैसला बहुत जल्द किया जाएगा और कहा कि वह सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ भारत को एक प्रभावी गढ़ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

जो खुद को देशभक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई : राहुल गांधी

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से कुल 146 सांसदों के निलंबन के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शुक्रवार को धरना दिया। जंतर-मंतर पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं।

इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में दो युवा कूदकर अंदर आ गए। उन्हें कूदते हुए हम सबने देखा। वे अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया, भाजपा के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देश भक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई। वे अंदर कैसे आए? संसद के अंदर वे गैस का सिलेंडर ले आए? उन्होंने ये विरोध क्यों किया? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी! इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है।

राहुल ने कहा कि हम सब विपक्ष के नेता और विपक्ष के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, उतना इंडिया गठबंधन मोहब्बत फैलाएगा।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद डीन एल्गर ने किया सन्यास का ऐलान

सेंचुरियन। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व टेस्ट कप्तान डीन एल्गर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है। वह भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। 36 साल के एल्गर ने अपने निर्णय के बारे में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका को बता दिया है। एल्गर से सीरीज शुरू होने से पहले ही झटका दिया है। हालांकि, वह भारत के खिलाफ दोनों टेस्ट खेलते दिखेंगे।

पहला टेस्ट सेंचुरियन में 26 दिसंबर से और दूसरा टेस्ट तीन जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट के बाद एल्गर के 12 साल लंबे करियर का अंत हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने 80 से भी ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं और 5000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में 17 मैचों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी भी कर चुके हैं।

एल्गर ने एक भावुक पोस्ट में लिखा- जैसा कि सब कहते हैं कि सभी अच्छी चीजों का अंत हो जाता है और भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज मेरी आखिरी सीरीज होगी क्योंकि मैंने इस खूबसूरत खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है। एक ऐसा खेल जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है। केपटाउन टेस्ट मेरा आखिरी टेस्ट होगा। दुनिया में मेरे पसंदीदा स्टेडियम में आखिरी मैच खेलूंगा। यह वही स्टेडियम है जहां मैंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट रन बनाए थे और वहीं मैं आखिरी टेस्ट भी खेलूंगा।

एल्गर ने कहा, क्रिकेट खेलना हमेशा से मेरा सपना रहा है लेकिन अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना सबसे अच्छी बात रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 साल तक ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त करना मेरे सपने से परे है। यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 242 अंक चढ़ा निफ्टी 21,300 के पार

नई दिल्ली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को देसी शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 242 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 94 अंक की बढ़त दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक क्रमशः 0.74 प्रतिशत और 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ बेंचमार्क से आगे निकल गए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 241.86 अंक यानी 0.34 फीसदी की बढ़त के साथ 71,106.96 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 70,713.56 और 71,259.55 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 94.35 अंक यानी 0.44 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 21,349.40 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 21,232.45 और 21,390.50 के रेंज में कारोबार हुआ।

सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर

नई दिल्ली। कमर्शियल एलपीजी के 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतों में प्रति सिलेंडर 39.50 रुपये की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1757 रुपये होगी। बता दें कि बीती 1 दिसंबर को ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 21 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। अब सरकार के इस कदम से रेस्तरां और होटल इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1710 रुपये रहेगी। वहीं कोलकाता में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 1868.50 हो जाएगी। चेन्नई में यह कीमत 1929 रुपये होगी। बता दें कि राज्य स्तर पर टैक्स में अंतर के चलते कीमतों में यह बदलाव दिखता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (सीपी) को एलपीजी की कीमतों के लिए बेंचमार्क माना जाता है।

जोमैटो 2 अरब डॉलर में नहीं खरीदेगी शिपरॉकेट

नईदिल्ली। जोमैटो ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि उसने 2 अरब डॉलर में डिलीवरी प्लेटफॉर्म शिपरॉकेट के अधिग्रहण की पेशकश की है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में इस खबर को गलत बताया। फाइलिंग में, कंपनी ने कहा, मेनस्ट्रीम मीडिया में इस तरह की खबर चल रही है कि जोमैटो ने शिपरॉकेट के अधिग्रहण के लिए 2 अरब डॉलर की पेशकश की है। फाइलिंग में आगे कहा गया है, हम इस बयान का खंडन करते हैं और निवेशकों को बाजार में चल रही ऐसी गलत खबरों के प्रति आगाह करना चाहते हैं। हम अपने मौजूदा व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस समय किसी भी अधिग्रहण की कोई योजना नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने भी इस रिपोर्ट का खंडन किया।

एग्रीटेक से जुड़े स्टार्टअप फसल ने जुटाए 100 करोड़

नईदिल्ली। कृषि प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप फसल ने अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए निवेशकों से 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। फसल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, कंपनी ने सीरीज-ए वित्त कोष चरण में 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बयान के अनुसार, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार विस्तार के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। फसल की स्थापना 2018 में की गई थी। यह खेती, फसल-विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए एआई (कृत्रिम मेधा), फसल विज्ञान और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) का इस्तेमाल करता है जिससे संसाधन अनुकूलन और उच्च कृषि उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके।

अर्थव्यवस्था की तेज होती रफ्तार

डॉ अश्विनी महाजन

भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग द्वारा 30 नवंबर 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7.6 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा, जो 2022-23 की दूसरी छमाही की संवृद्धि दर 6.2 प्रतिशत से कहीं ज्यादा रही। गौरतलब है कि इस तिमाही में भारत की चालू कीमतों पर जीडीपी 71.66 लाख करोड़ रुपये रही। इसका मतलब यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय इस तिमाही में 2.01 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। सितंबर माह में डॉलर की औसत बाजार कीमत 82.5 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से आज भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2,436 डॉलर प्रति वर्ष है। यदि जीडीपी की अर्द्ध-वार्षिक वृद्धि के आंकड़े देखें, तो 2023-24 में मार्च से सितंबर की अवधि में जीडीपी वर्ष 2022-23 के पूर्वार्द्ध की तुलना में वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत दर्ज की गयी। यदि जीडीपी बढ़ोतरी की यह रफ्तार बरकरार रहती है, तो जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि के साथ सितंबर 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 3,600 डॉलर प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 1,500 डॉलर प्रति वर्ष ही थी।

भारत में जीडीपी की संवृद्धि में हालांकि सभी क्षेत्रों का योगदान रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तिमाही की मूल्य संवृद्धि में सबसे बड़ा हिस्सा मैनुफैक्चरिंग का रहा है। यह हिस्सा 13.9 प्रतिशत है। वृद्धि की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कंस्ट्रक्शन का रहा है, जहां 13.3 प्रतिशत की दर से संवृद्धि देखी गयी है। तीसरा मुख्य क्षेत्र बिजली, गैस, जल आपूर्ति

और अन्य उपयोगी सेवाओं का रहा है, जहां 10.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गयी है। उसके बाद खनन का स्थान है, जहां 10 प्रतिशत की दर से संवृद्धि दर्ज की गयी। देखा जाए, तो सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी बहुत उल्लेखनीय नहीं है। चिंता का विषय है कि इस तिमाही में कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि बहुत कम 1.2 प्रतिशत दर्ज की गयी है। ऐसा किसी मौलिक दोष के कारण नहीं हुआ है, बल्कि मानसून की कमी के कारण है। मैनुफैक्चरिंग में वृद्धि भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' की नीति की सफलता की ओर इंगित करती है।

कुछ खास संकेतकों को देखा जाए, तो कोयला, स्टील, सीमेंट, खनन, बिजली उत्पादन इत्यादि में भी खासी संवृद्धि दर दिखाई दे रही है। कोयले के उत्पादन में 16.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है, सीमेंट उत्पादन में यह बढ़ोतरी 10.2 प्रतिशत है। स्टील उत्पादन में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दे रही है। खनन में भी 11.5 प्रतिशत संवृद्धि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की भी संख्या बढ़ी है और रेलवे के भी यात्रियों के आंकड़े बेहतर संख्या बता रहे हैं। हवाई यात्रियों की संख्या में 22.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बैंकों में जमा भी 11.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में 13 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज हुई है। सभी आंकड़े देश में बेहतर होते आर्थिक वातावरण की ओर इंगित कर रहे हैं। समझना होगा कि मैनुफैक्चरिंग में वृद्धि का सीधा असर रोजगार पर पड़ता है। इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं सेवा क्षेत्र से कहीं ज्यादा होती हैं। भारत में जहां आर्थिक संवृद्धि की दर 7.6 प्रतिशत है, चीन में यह मात्र 4.9 प्रतिशत दर्ज की गयी है, जबकि रूस में यह दर 5.5 प्रतिशत और अमेरिका में 5.2 प्रतिशत है। जर्मनी, जो इस समय जीडीपी की दृष्टि से भारत से एक स्थान ऊपर है, वहां जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की दर से गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत की पिछले छह महीने की जीडीपी 142.33 लाख करोड़ रुपये, यानी 1.736 खरब डॉलर है। यदि जीडीपी में वर्तमान दर से वृद्धि होती है, तो भारत की वार्षिक जीडीपी 3.5 खरब डॉलर पहुंच जायेगी, और जर्मनी की वर्तमान जीडीपी 4.1 खरब डॉलर में यदि अनुमानों के अनुसार 0.4 प्रतिशत की कमी दर्ज होती है, तो भारत की जीडीपी जर्मनी की जीडीपी (4.08 खरब डॉलर) से मात्र 600 अरब डॉलर ही कम रह जायेगी। विकास की वर्तमान दर यदि कायम रहती है, तो भारत ढाई साल से भी कम समय में जर्मनी की जीडीपी से आगे निकल सकता है।

अब मायूस क्यूँ हो उसकी बेवफाई पर .... खुद ही तो कहते थे की वो सबसे जुदा है....

छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता और विपक्ष के प्रमुख पदों पर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे अनुभवी नेताओं के हांथों नेतृत्व है।विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन,सीएम विष्णुदेव साय तथा नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत तीनों अटलजी, नरेंद्र मोदी तथा डॉ मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैँ।डा.रमन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के साथ ही छग के 15 सालों तक सीएम रहे हैं।रमन सिंह ने राजनीति पारी की शुरू आत जनसंघ के यूथ विंग

से की थी। इन्होंने कवर्धा की नगर पालिका में वार्ड मेंबर,विधायक,संसद में बहुत से महत्वपूर्ण पद संभाले है।1999 में संसद के सदस्य रहते हुएअटलजी के मंत्रिमंडल में वाणिज्य राज्य मंत्री के तौर भी काम किया है।साथ ही इन्होंने देश को इज़राइल,नेपाल, फिलिस्तीन और दुबई में भारतीय व्यापार मेले का नेतृत्व भी किया है।इधर छग के चौथे सीएम विष्णु देव साय बने हैं।उन्होंने 2020 से 2022 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।वे मोदी के 2014-2019के पहले मंत्रिमंडल में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री थे। कुन कुरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रति निधित्व करने वाले 16वीं लोकसभा के सदस्य थे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ चरण दास महंत को छग विस में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है।पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. महंत कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हैं।भूपेश सरकार में वह विस अध्यक्ष कादायित्व संभाल रहे हैँ ।2009 में 15वीं लोकसभा के लिए वह प्रदेश से अकेले कांग्रेसी लोकसभा सदस्य चुने गए थे।वर्तमान में सक्ती से विधायक हैं।महंत का राजनीतिक सफर मप्र विधानसभा से शुरू हुआ।1980 से 1990 तक दो कार्यकाल में विधायक रहे।1993 से 1998 के बीच वह मप्र सरकार में मंत्री रहे।1998 में उन्हें 12वीं लोकसभा के लिए चुना गया।1999 में भी13वीं लोकसभा के लिए वे चुने गए। 2009 में वह 15वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए। महंत ने केंद्र में डॉ मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री,उद्योग खाद्यऔर प्रसंस्करण का पदभार भी संभाल चुके हैँ।

साय की टीम बनी,फिर भाजपा ने चौंकाया...?

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब साय मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण देखा जाए तो सीएम सहित रामविचार नेताम और केदार कश्यप एस सी वर्ग से हैं तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल सामान्य वर्ग से हैं।एससी वर्ग से केवल एक दयाल दास बघेल को शामिल किया गया है तो पिछड़ा वर्ग से डिप्टी सीएम अरुण साव सहित 6लोग लखन लाल देवांगन, ओपी चौधरी, श्यामबिहारी जाय सवाल, टँकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े शामिल किये गये हैं।वैसे सीएम चयन में जैसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने चौँकाया था वैसे ही मंत्रि मंडल में भी भाजपा के धरमलाल कौशिक,अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर,राजेश मुणत,लता उसेंडी, रेणुका सिंह,गोमती साय आदि को शामिल नहीं करना भी चर्चा में है।

किरणदेव बने भाजपा अध्यक्ष, अरुण को हटाने की जल्दी क्या थी.?

छग में भाजपा की सरकार बन गई और चुनाव के कुछ समय पहले बने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया गया है और उनके स्थान पर

जगदलपुर के विधायक तथा पूर्व महापौर किरण देव को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है।वैसे संभवतःअरुण साव का इतने कम समय का प्रदेश अध्यक्ष बनने का रिकार्ड बन गया है। लोकसभा चुनाव तक इन्हें रखा जा सकता था,डिप्टी सीएम तो वे लोस चुनाव के बाद भी बनाये जा सकते थे।पर अचानक उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर,प्रदेश अध्यक्ष पद से इतनी जल्दी हटाने के पीछे क्या कारण है?यह तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व या संघ ही अच्छे से जनता होगा?

आईएएस दयानन्द सीएम के सचिव....

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेजतर्रार आईएएस पांडे दयानंद को सेक्रेटरी बनाया गया है।वहीं सीएम के ओएसडी तय हो गए हैं।पी. दयानंद मूलत: बिहार राज्य के सासाराम जिले के रहने वाले है।वह 2006 बैच के छग कैडर के आईएएस है। बिलासपुर, कोरबा,कवर्धा और सुकमा यानि चार जिलों की कमान भीसम्हाल चुके है।उन्हें नक्सल क्षेत्र में काम करने का भी अनुभव है।आईएएस प्रशिक्षु अवधि दंतेवाड़ा जिला पंचायत में सीईओ रहते हुए पूरा किया था।इसके बाद वह सुकमा के कलेक्टर बने।उन्होंने एजुकेशन हब की नींव रखी।तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते रहे है।वे भाजपा के एक बड़े राष्ट्रीय नेता के भतीजी दामाद हैं ऐसा पता चला है?राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में राज्य प्रशासनिक सेवा के डॉ सुभाषसिंह राज निजी स्थापना में ओएसडी रूप में उमेश अग्रवाल दिल्ली,रवि कांत मिश्रा तथा निज सचिव के रूप में दीपक अंधारे को पदस्थ किया गया है।

धान खरीदी,जांजगीर पुलिस की अच्छी पहल.....

भाजपा की सरकार राज्य में बन गई है,अपने घोषणा पत्र के अनुसार धान 3100/?में खरीदने की शुरुआत हो गई है।भूपेश सरकार 25से 2600में खरीदी करती थी।जाहिर है कि किसानों के पास अब अधिक राशि आएगी। ऐसे में किसानों को अपनी मेहनत की राशि सुरक्षित रखने सतर्कता की जरूरत होगी। जांजगीर पुलिस के मुखिया,छत्तीसगढ़िया एसपी विजय अग्रवाल ने पोस्टर जारी कर किसानों को सतर्क करने का प्रयास किया है।पुलिस ने जिले के शहरी,ग्रामीण क्षेत्रों के सार्व जनिक स्थानों पर पोस्टर को चस्पा भी करवाया है।यह सराहनीय पहल तो है ही साथ में पुलिस का समाज के सरोकार से जुड़ने का भी एक बड़ा उदाहरण है।

और अब बस...

- छग में कोई पूर्व सीएम पहली बार विस अध्यक्ष बने हैँ ।
- रामविचार नेताम छग के पहले भाजपा के प्रोटम स्पीकर बने।
- कभी किसी मंत्री के पीए थे,अब उसी मंत्री के साथ ही मंत्री पद की शपथ भी ली है।

कोरोना को लेकर केन्द्र के गाईडलाईन का सख्ती से करें पालन

रायपुर। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कलेक्टरों के साथ प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव और रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के संभावित लक्षण वाले लोगों के सैम्पल की जांच प्रतिदिन ज्यादा-ज्यादा से संख्या में करने को कहा। उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की जांच के लिए अस्पतालों में मॉक-ड्रिल भी करने को कहा। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी कलेक्टरों से कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। शासन की हर योजना लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग जनता के हित में करें। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से रूके हुए कार्यों पर विशेष ध्यान दें। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आप लोग नई ऊर्जा और उत्साह से काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने वीसी में कहा कि सरकार गठन के शुरूआती आठ दिनों में ही राज्य में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शासन और प्रशासन को मिलकर इन फैसलों का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना है।

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहां मंत्रालय महानदी भवन स्थित उनके कार्यालय में मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों ने मुलाकात की । मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को पुष्पगुच्छ भेंटकर व मिठाई खिला कर बधाई दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव व श्री विजय शर्मा, श्री रामविचार नेताम, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री दयालदास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्यामबिहारी जायसवाल, श्री ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्री टंकराम वर्मा, उपस्थित रहे।

प्रमुख समाचार
छत्तीसगढ़/राजधानी

बिजली बिल हाफ योजना बंद नहीं होगी-उपमुख्यमंत्री शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना लागू की थी। इस योजना के सभी प्रदेश के सभी वर्गों के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की जा रही थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ इस योजना को लेकर संशय का माहौल बना हुआ है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया था। ऐसे में इस बात की संभावना लगातार व्यक्त की जा रही थी कि नई सरकार इस योजना को बंद कर देगी।

इस बीच बिजली बिल हाफ योजना को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस के नेता डिप्टी सीएम विजय शर्मा एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आते ही बिजली बिल हाफ योजना बंद की जा रही है। कांग्रेस के वीडियो पर डिप्टी सीएम शर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने मीडिया को वही वीडियो दिखाते हुए कहा कि गौर से सुनिए मैं बिजली बिल हाफ योजना बंद करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा है बिजली हाफ बंद होगा। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की बिजली बिल हाफ योजना में कई विसंगति है उसे दूर किया जाएगा। डिप्टी सीएम शर्मा के इस बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि भाजपा सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी।

पिछला चुनाव हो गया, अब आगे बढ़ना हैं: शैलजा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई. इसमें विधानसभा चुनाव 2023 में मिली हार पर मंथन हुआ. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत समेत पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हुए. बैठक में विधानसभा चुनाव में हारे हुए विधायकों से खुलकर बातचीत हुई. साथ हीआगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई. कांग्रेस स्थापना दिवस और क्राउड फंडिंग को लेकर भी चर्चा हुई. बताया जा रहा है कि, 28 दिसंबर को नागपुर में कांग्रेस स्थापना दिवस पर बड़ा कार्यक्रम करेगी. छत्तीसगढ़ से 25 हजार कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यकारिणी बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि, कांग्रेस ने क्रॉउड फंडिंग का अभियान छेड़ा है. 28 दिसंबर को कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है. इस दिन नागपुर में एक बड़ी महारैली होगी. रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेता शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ से हमारे लोग वहां जाना चाहते हैं. 28 दिसंबर को स्थापना दिवस पर कांग्रेस के हर स्थानों पर कांग्रेस का झंडा फहराएंगे. लोकसभा की तैयारियों को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा, पिछला चुनाव हो गया अब आगे बढ़ाना है. जितने विधायक है वह क्षेत्र के दौरे पर है. एक बार फिर काम पर हम लग रहे हैं. लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई है. कुछ लोग पार्टी में है जो सुझाव देते हैं.

साक्षी मलिक का संन्यास खेल इतिहास का "काला अध्याय"

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि पहलवान बेटियों से यौन शोषण के आरोपी, भाजपा सांसद ब्रज भूषण के असिस्टेंट व 'नॉमिनी', संजय सिंह के चुनाव के बाद कुश्ती में ओलिंपिक पद जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान व किसान की बेटी साक्षी मलिक द्वारा खेल से सन्यास की घोषणा भारत के खेल इतिहास का "काला अध्याय" है। चैंपियन महिला पहलवानों के साथ 'ज्यादती व अन्याय' के लिए सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की आवाज उठाने वाली बेटियों को रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर घर भेज दिया जाएगा, और दोषी सत्ता की शहतीरों से कहकहे लगाएंगे, और बेटियों की बेबसी तथा लाचारी का मजाक उड़ाएंगे। शायद इसीलिए यौन शोषण के आरोपी, ब्रजभूषण सिंह ने कुश्ती संघ के चुनाव के बाद कहा, "दबदबा था, दबदबा रहेगा"। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि रोहतक के मोखरा गाँव में जन्मी हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार की बेटी देश के लिए ओलिंपिक मेडल लाने तक पहुँची, और आज मोदी सरकार के "दबदबे" ने उसे वापस घर जाने पर मजबूर कर दिया। देश की पहलवान बेटियाँ न्याय मांगने के लिए 39 दिन तक तपती दोपहरी में जंतर-मंतर पर बैठ संसद के दरवाजे पर दस्तक देती रहीं, सिसकती रहीं, पर भाजपा सरकार ने उन्हें न्याय नहीं दिया।

व्यवहार न्यायाधीश पद के लिए साक्षात्कार 2 से 5 जनवरी एवं 8 से 11 जनवरी तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2022 (विधि एवं विधायी कार्य विभाग) के 48 विज्ञापित पद हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 जून 2023 को किया गया और परीक्षा परिणाम 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया। इस लिखित परीक्षा के प्राप्तांको एवं अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्धता के अधार पर कुल 152 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है। आयोग द्वारा चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 02 जनवरी 2024 से 05 जनवरी 2024 एवं 08 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि नोवेल कोराना वायरस (ब्वअपक-19) के सक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अन्यर्थी फेसमास्क एवं हेड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। व्यवहार न्यायाधीश के पदों के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली- पूर्वान्ह 10 बजे से 01 बजे तक तथा द्वितीय पाली- अपरान्ह 02 बजे से 05 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा।

आर टी आई पोर्टल में स्व पंजीयन करने मंत्रालय और विभागाध्यक्ष में दिया गया प्रशिक्षण

रायपुर। आरटीआई पोर्टल में जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्व पंजीयन करने के विषय पर शुक्रवार को नया रायपुर स्थित मंत्रालय भवन और विभागाध्यक्ष भवन में प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में राज्य सूचना आयोग के सचिव श्री जी आर चुरेन्द, सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव और नोडल अधिकारी श्रीमती मेरी खेस, राज्य सूचना आयोग की अवर सचिव श्रीमती गीता दीवान, अनुभाग अधिकारी श्री अतुल वर्मा, एन आई सी के श्री अशोक मौर्य की टीम ने जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण कार्यशाला में डेमो के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल में स्व पंजीयन की प्रक्रिया, ऑन बोर्डिंग के बाद आवेदनों का निराकरण, अपलोडिंग की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण में जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारियों को ऑनबोर्ड आवेदन देखना और उसके निराकरण की जानकारी दी गई। ऑनलाइन शुल्क की मांग करने की प्रक्रिया बताई गई। प्रशिक्षण कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग के सचिव श्री जी आर सुरेंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं राज्य शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में स्व पंजीयन का कार्य दिसंबर माह में पूर्ण करना है।

प्रदेश कांग्रेस की बैठक संपन्न

कांग्रेस संगठन के 138 साल पूर्ण होने पर जिला संगठन मुख्यालय एवं बूथ स्तर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम

रायपुर/22 दिसंबर 2023। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारणी और कांग्रेस के विधायकों की बैठक प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, संयुक्त सचिव एवं सह प्रभारी विजय जांगिड़ की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में स्वागत भाषण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दिया। बैठक में कांग्रेस संगठन के 138 साल पूर्ण होने पर जिला संगठन

मुख्यालय एवं बूथ स्तर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करने, क्राउडफंडिंग अभियान में सहयोग करने, नागपुर में आयोजित स्थापना दिवस की महारैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने एवं लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पूर्व मंत्रीगण अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, डॉ. शिवकुमार डहरिया, ताम्रध्वज साहू, मो. अकबर, गुरू रूद्र कुमार, पूर्व मंत्री एवं विधायक कवासी लखमा, पूर्व मंत्री एवं विधायक अनिला भेड़िया, पूर्व मंत्री एवं विधायक उमेश पटेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, विधायकगण विद्यावति सिदार, उत्तरी गनपत जांगड़े, फूलसिंह राठिया, राघवेन्द्र कुमार सिंह, रामकुमार यादव, बालेश्वर साहू, शेषराज हरवंश, द्वारिकाधीश यादव, संदीप साहू, इन्द्र साव, जनक राम ध्रुव, अंबिका मरकाम, कुंवर सिंह निषाद, हर्षिता स्वामी बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, इंद्रशाह मंडावी, सावित्री मंडावी, लखेश्वर बघेल, विक्रम मंडावी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिश देवांगन, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्षगण प्रतिमा चंद्राकर, अरूण सिंघानिया, अंबिका मरकाम, पी.आर. खुंटे, बीरेश ठाकुर, डॉ. जे.पी. श्रीवास्तव, महामंत्रीगण प्रशांत मिश्रा, दीपक मिश्रा, नरेश ठाकुर, चंद्रशेखर शुक्ला, डॉ. थानेश्वर पटिला, राजेन्द्र साहू, सकलेन कामदार, जितेन्द्र साहू, द्वितेन्द्र मिश्रा, सीमा वर्मा, शाहिद खान, दीपक दुबे, सुबोध हरितवाल, कार्यसमिति सदस्य गण शकुन डहरिया, गंगा पोटाई, शिव नेताम, सुरेन्द्र जायसवाल, भोलाराम साहू, महमूद अली उपस्थित थे।

सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस का धरना

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विपक्षी सांसदों के निलंबन कार्यवाही एवं लोकतंत्र की हत्या के विरोध में एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन किया गया। राजधानी रायपुर में एआईसीसी महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, अंबिका सिंहदेव, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, रायपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे, राजेन्द्र तिवारी, अमरजीत चावला, किरण सिन्हा, विक्रम मंडावी, पूनम पाण्डेय, मेहमूद अली, मदन तालेड़ा, शारिक रईस खान, करूणा कुर्रे, संगीता दुबे, सुनीता शर्मा, भोजकुमारी यदु, नीलिमा मिश्रा, पूजा देवांगन, सुनील भुवाल, माधव छुरा, प्रवीण चंद्राकर, हाजी फहीम खान, सागर, राजू सोनी, श्याम सिक्का, गौतम यादव, इम्मानुएल मसीह, मोहन साहू, भीम यादव, सन्नी तुमरेकी, उत्तम सहा, मनहरन यादव, जयंत पाठक, विष्णु सिंह, अनिल कुमार सोनी, अमीता झा, अंजली साहू, कमलाकांत शुक्ल, जगदीश आहूजा, अविनय दुबे, सोमन लाल ठाकुर, संजीव कुमार, सुर्या शुक्ला, दिलीप गुप्ता, विकास अग्रवाल, शंकर जंघेल, महावीर, विजयकुमार, धमेन्द्र सोनी, राजेन्द्र साहू, अप्राजीत तिवारी, प्रदीप देवांगन उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.